हिंदी दैनिक

कलम की पहल

PRGI NO. UAHIN/25/A1323

वर्ष : 02 अंक : 161 पृष्ठ : 08 मूल्य : 1 रूपए नैनीताल, शनिवार, 29 नवंबर, 2026

E-mail: kalamkipahaluk@gmail.com Website: kalamkipahal.com

मुख्यमंत्री ने की राज्य की महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा

गतिमान परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने तथा नई परियोजनाओं को शीघ्र शुरू करने के दिए निर्देश

क्षेत्र विशेष की पहचान को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाई जाएं परियोजनाएं : मुख्यमंत्री

हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण विकास कार्य दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य



देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड निवेश और आधारभूत संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की पांचवीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने हरिद्वार गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर तथा शारदा रिवरफ्रंट कॉरिडोर सहित राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गतिमान परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाई जाए तथा जिन परियोजनाओं को शीघ्र प्रारंभ किया जा सकता है, उनके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण कर कार्य शुरू कराए जाएं। उन्होंने कहा कि आगामी एक माह के भीतर कुछ परियोजनाओं के कार्य धरातल पर दिखाई देने चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं को क्षेत्र विशेष की पहचान, स्थानीय संस्कृति, धार्मिक एवं प्राकृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया जाए। परियोजनाओं के विकास में स्थानीय विशिष्टताओं का समावेश किया जाए, ताकि क्षेत्र की पहचान बनी रहे और पर्यटन एवं रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिल सके।

बैठक में अवगत कराया गया कि हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के अंतर्गत 3,297 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें लगभग 495 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाएं क्रियान्वयन के चरण में हैं। प्रशासनिक मार्ग के विकास का 75 प्रतिशत, हरकी पैड़ी के उत्तरी क्षेत्र में विकास कार्यों का 70 प्रतिशत, हरकी पैड़ी एवं सुभाष घाट के पुनर्विकास का 50 प्रतिशत तथा रोड़ी बेलवाला क्षेत्र के पुनर्विकास का 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। मां मनसा देवी एवं मां चंडी देवी मंदिरों के पहुंच मार्गों के विकास का क्रमशः 55 एवं 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इन कार्यों को दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। सतीकुंड के पुनर्विकास का 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसे अप्रैल 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के अंतर्गत 3,456 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें 274 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाएं क्रियान्वयन के चरण में हैं। जानकी झूला के समीप एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के निर्माण का 39 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसे जून 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

दीपथून स्तंभ पर शनिवार को दीपक जलाने का आदेश, मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड सस्पेंड; SC का ताबड़तोड़ ऐक्शन



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर विवादित दीपथून स्तंभ पर शनिवार को पारंपरिक दीपक जलाने का आदेश दिया है। साथ ही, अदालत ने अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के ट्रस्ट बोर्ड को निलंबित कर मंदिर का प्रशासन अपने नियंत्रण में ले लिया है। इसके लिए 2 सदस्यीय समिति गठित की गई है। अदालत ने मंदिर और पहाड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को सौंप दी है। पीठ ने निर्देश दिया कि दीपथून पर दीपक जलाने के लिए 24 नवंबर को उचिपिल्लैयार मंडपम में प्रज्वलित दीपक की लौ का इस्तेमाल किया जाए। इस धार्मिक आयोजन में सभी श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे। दीपक जलाने की जगह दरगाह से कम से कम 50 मीटर दूर रखने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं, दरगाह और उसके परिसर की सुरक्षा तमिलनाडु पुलिस करेगी।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश 20 नवंबर के अपने पुराने निर्देश का पालन नहीं होने पर सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP), मदुरै के जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया है। पीठ ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और अधिकारियों के बीच हुए ईमेल, फोन कॉल और संदेशों का ब्योरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि उसके आदेशों का पालन हर हाल में होना चाहिए। ये निर्देश राज्य सरकार, प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित धार्मिक संस्थाओं सभी पर बाध्यकारी हैं। इन्हें बातचीत या मोलभाव का विषय नहीं बनाया जा सकता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। पीठ ने कहा कि राज्य का प्रशासनिक तंत्र पहली नजर में संवैधानिक अव्यवस्था की स्थिति में दिखाई देता है। कार्यपालिका के अधिकारियों की ओर से जानबूझकर अदालत के आदेशों का पालन नहीं करना गंभीर मामला है और इससे सख्ती से निपटना जरूरी है। अदालत ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने या उसके अधिकार को चुनौती देने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसका पद कितना ही बड़ा क्यों न हो।

डिलिमिटेशन बिल पर मोदी सरकार का सपोर्ट करेगी शरद पवार की NCP, INDIA अलायंस में बड़ी फूट



मुंबई। शरद पवार की एनसीपी (एसपी) संसद में आने जा रहे डिलिमिटेशन बिल पर मोदी सरकार का सपोर्ट करने जा रही है। अब तक इंडिया अलायंस का हिस्सा रहने वाली एनसीपी (एसपी) के रुख बदलने से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगेगा। कांग्रेस समूचे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एनसीपी एसपी ने डिलिमिटेशन बिल सपोर्ट करने का फैसला किया है। यह इंडिया अलायंस में बड़ी फूट मानी जा रही है। मुंबई के अस्पताल में भर्ती शरद पवार से मुलाकात करने के बाद एनसीपी एसपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने ऐलान किया है। इससे पहले, पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी यह संकेत दे चुकी थीं कि उनकी पार्टी बिल के पेश होने के बाद फैसला लेगी। इससे माना जा रहा था कि उनकी पार्टी बिल को सपोर्ट कर सकती है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, शरद पवार के साथ अपनी बातचीत पर NCP-SP नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, 'बातचीत हमारी पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड के बारे में नहीं थी। आम तौर पर यह कहा जा रहा था कि डिलिमिटेशन प्रोसेस एक संवैधानिक जरूरत है। डिलिमिटेशन प्रोसेस को सपोर्ट करने का फैसला किया गया है, और हम सच में इसका सपोर्ट करेंगे। हम डिलिमिटेशन को सपोर्ट करेंगे। सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को कहा था कि वह संसद की विशेष बैठक में विपक्ष की रणनीति पर चर्चा के लिए शनिवार को बुलाई गई 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस' (इंडिया) की बैठक में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि उनके पिता शरद पवार अस्वस्थ हैं।

'एक विशेष समुदाय की नियुक्ति, SC-ST की अनदेखी'.. पूर्व CJI बीआर गवई ने कॉलेजियम सिस्टम पर उठाए सवाल



नई दिल्लीः भारत के पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति तथा तबादलों में सामाजिक प्रतिनिधित्व और विविधता के सिद्धांतों की अनदेखी पर गंभीर चिंता जताई है. पूर्व चीफ जस्टिस ने कॉलेजियम सिस्टम के कामकाज को लेकर ही सवाल उठा दिए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि कॉलेजियम एक विशेष समुदाय को नियुक्तियों में प्राथमिकता दे रहा है. उन्होंने कहा कि उनके चीफ जस्टिस रहते कॉलेजियम में एससी, एसटी ओबीसी, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व का ख्याल रखा जाता था. 27 नवंबर 2026 को लिखे पत्र में जस्टिस गवई ने कहा है कि हाल के घटनाक्रमों से ऐसा प्रतीत होता है कि कॉलेजियम व्यवस्था में योग्यता और समावेशिता के सिद्धांतों की अनदेखी हो रही है और एक विशेष समुदाय को नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जा रही है. जस्टिस गवई ने कहा कि उनके CJI रहते हुए कॉलेजियम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता था. उन्होंने संसद में दिए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2018 से नियुक्त 715 हाईकोर्ट जजों में केवल 22 SC, 16 ST, 89 OBC और 37 अल्पसंख्यक समुदायों से थे.

उन्होंने कहा कि जनवरी 2021 से जनवरी 2026 के बीच सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करीब 80 फीसदी रहा, जबकि OBC समुदाय का प्रतिनिधित्व लगभग 14 फीसदी बताया गया. जस्टिस गवई ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष समुदाय के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर भी सवाल उठाए और कहा कि देश की आबादी में 5 फीसदी से कम हिस्सेदारी रखने वाले समुदाय का सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व 40 फीसदी से अधिक हो गया है. उन्होंने हाईकोर्ट के जजों के तबादलों में भी असमानता का आरोप लगाया. उनके मुताबिक, एक मेहनती और मेधावी मुख्य न्यायाधीश को छोटे हाईकोर्ट में भेजा गया, जबकि दूसरे जज को बड़े और प्रतिष्ठित हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई.

समंदर की सियासत में भारत बना बॉस !

जयशंकर ने हिंद महासागर के 23 देशों को एकजुट कर खींची नई लकीर



नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 27 नवंबर को कहा कि हिंद महासागर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और संपर्क के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र के सभी तटीय देशों को अपने लोगों के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर 'सार्थक सहयोग' की दिशा में काम करना चाहिए. जयशंकर ने 'हिंद महासागर रिम एसोसिएशन' (आईओआरए) के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण 'भू-राजनीतिक बदलावों' के दौर में इस संगठन को अपनी सामूहिक आवाज मजबूत करनी चाहिए और एक क्षेत्रीय मंच के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बनाना चाहिए. भारत ने आईओआरए के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में इस सम्मेलन की मेजबानी की. इस संगठन में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, सोमालिया, ओमान, यमन, बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड सहित 23 देश शामिल हैं. जयशंकर ने बैठक में कहा, 'हिंद महासागर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, संपर्क और आर्थिक समृद्धि के लिहाज से काफी महत्व रखता है. यह अपार विविधता, अवसरों और साझा चुनौतियों वाला क्षेत्र भी है.' उन्होंने कहा कि आईओआरए के प्रति भारत का दृष्टिकोण और संगठन की अध्यक्षता के दौरान भारत की प्राथमिकताएं 'महासागर' दृष्टिकोण से निर्देशित हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल मार्च में मॉरीशस की यात्रा के दौरान ग्लोबल साउथ के साथ भारत के जुड़ाव के लिए 'महासागर' दृष्टिकोण की घोषणा की थी.

'वोट चोर, गद्दी छोड़' वाले वीडियो पर हम रोक नहीं लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारत समिट 2026 के दौरान इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक के 'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारे से जुड़े सोशल मीडिया वीडियो हटाने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। याचिका में कार्यक्रम के आयोजन और उससे जुड़े घटनाक्रम की जांच कराने की मांग भी की गई थी।

याचिकाकर्ता का आरोप था कि यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने भारत की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप किया। उन्होंने हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के दौरान भारतीय सरकार की आलोचना करते हुए यह नारा लगाया था।

मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने की। पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया गया। कोर्ट ने पूछा, 'आप शिकायत दर्ज करा सकते थे। अनुच्छेद 32 के तहत याचिका क्यों?'

याचिकाकर्ता के वकील सैयद रिजवान अहमद ने कहा कि वे किसी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं चाहते, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में विदेशी नागरिक इस तरह की टिप्पणियां न करें।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि वायरल वीडियो प्रतीकात्मक रूप से प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए मेटा को इन वीडियो को हटाने का निर्देश दिया जाए। साथ ही तेलंगाना सरकार से यह आश्वासन भी मांगा गया कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों में विदेशी नागरिकों के भाषणों को नियंत्रित किया जाएगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी।



संस्कृत को घर-घर पहुंचाने की तैयारी, पुरस्कार और छात्रवृत्ति की रकम होगी दोगुनी

देववाणी के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार का बड़ा दांव, हर जिले में युवा सम्मेलन और विद्यालयों में संस्कृतमय प्रार्थना सभा की योजना

के.के.पी संवाददाता

चंपावत। संस्कृत को केवल विद्यालयों और धार्मिक आयोजनों तक सीमित रखने के बजाय जन-जन की भाषा बनाने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने पहल तेज कर दी है। संस्कृत संस्थानम की ओर से संचालित पुरस्कार और छात्रवृत्तियों की धनराशि दोगुनी करने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि आर्थिक प्रोत्साहन से विद्यार्थियों में संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ेगी और देववाणी को समाज की दिनचर्या से जोड़ा जा सकेगा।

संस्कृत संस्थानम के उपाध्यक्ष डॉ. नवीन चंद्र पंत और सचिव डॉ. विनय विद्यालंकार ने बताया कि संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई

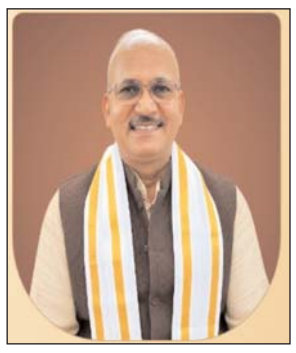



अधिकारियों की बैठक में भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए ठोस रणनीति पर चर्चा की गई। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में संस्कृत संस्थाओं के सहयोग से युवा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। संस्कृत के संरक्षण और उन्नयन में उल्लेखनीय काम करने वाली देश-प्रदेश की संस्थाओं का शैक्षिक भ्रमण भी कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आदर्श गांवों में भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों, राष्ट्र निर्माण और आदर्श दिनचर्या से जुड़ी गतिविधियों को लगातार प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम सामग्री, शैक्षिक उपकरण और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने पर भी जोर दिया गया है।

संस्कृत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के संकेत भी सामने आए हैं। डॉ. विनय विद्यालंकार ने बताया कि एक अमेरिकी संस्था ने संस्कृत दिवस आयोजित करने की इच्छा जताई है। उनके अनुसार संस्कृत केवल प्राचीन भाषा नहीं, बल्कि ज्ञान-विज्ञान, आचार-विचार और संस्कारों की समृद्ध परंपरा है, जिसके माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

नाबार्ड की ग्राम युवा शक्ति पहल : युवाओं को उद्यमिता एवं स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में सार्थक प्रयास

के.के.पी संवाददाता

भीमताल। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राष्ट्रव्यापी ग्राम युवा शक्ति अभियान के अंतर्गत बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज, भीमताल में जिला स्तरीय जागरूकता एवं प्रेरणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को उद्यमिता एवं स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें कौशल विकास, वित्तीय सहायता, सरकारी योजनाओं, तकनीकी मार्गदर्शन एवं विपणन संबंधी अवसरों से अवगत कराना रहा। कार्यक्रम में संस्थान के लगभग 100 युवा विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्री मुकेश बेलवाल ने राष्ट्रव्यापी ग्राम युवा शक्ति अभियान के



उद्देश्यों एवं महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान परिदृश्य में उद्यमिता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने युवाओं को नौकरी तलाशने के साथ-साथ रोजगार सृजनकर्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण पर्यटन, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र तथा तकनीक आधारित उद्यमों में उपलब्ध संभावनाओं की जानकारी दी। साथ ही, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं विकासात्मक पहलों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में विभिन्न बैंकों, विभागों, शिक्षण एवं विकास संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित योजनाओं, वित्तीय सहायता, कौशल विकास, तकनीकी नवाचार, उद्यम स्थापना एवं बाजार से जुड़ाव के अवसरों की जानकारी साझा की। वक्ताओं ने युवाओं को स्थानीय संसाधनों, नवाचार एवं आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए व्यवहार्य उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में अग्रणी जिला प्रबंधक श्री अमित बाजपेयी, नैनीताल जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक श्री दीपक भट्ट, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की शाखा प्रबंधक श्रीमती ममता कुमारी, बिरला संस्थान के कंप्यूटर विज्ञान विभागाध्यक्ष श्री अभय कुमार शर्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाध्यक्ष डॉ. शिली बिष्ट, विद्युत अभियांत्रिकी विभागाध्यक्ष श्री सौरव जोशी, सहायक प्राध्यापक श्री रोहित चतुर्वेदी, टेरी के प्रतिनिधि श्री विजय सिंह डंगवाल, रामनगर किसान उत्पादक संगठन के अध्यक्ष श्री पंकज सुयाल, मेरा युवा भारत के जिला युवा कार्यालय से श्री विनोद बोरा, दूरदर्शन समाचार उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार श्री गितेश त्रिपाठी तथा जन शिक्षण संस्थान, भीमताल के निदेशक श्री गोपाल जी उपस्थित रहे।

एक नजर

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना के नाम से संचालित होगी निराश्रित महिला भरण-पोषण अनुदान योजना

के.के.पी संवाददाता/देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार का एकल महिलाओं के सम्मान एवं आर्थिक संबल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निराश्रित महिलाओं के कल्याण एवं उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित भरण-पोषण अनुदान योजना का नाम संशोधित कर मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना कर दिया गया है। इस संबंध में सचिव, उत्तराखण्ड शासन डॉ. श्रीधर बाबू अद्धांकी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड को प्रेषित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि निराश्रित विधवा भरण-पोषण अनुदान तथा परित्यक्ता विवाहित महिलाओं एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु संचालित भरण-पोषण अनुदान योजना का नाम संशोधित करते हुए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना किया गया है। राज्य सरकार का यह कदम एकल महिलाओं को सम्मानजनक पहचान प्रदान करने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आज निकलेगी जागरूकता रैली और मशाल जुलूस

के.के.पी संवाददाता। भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में संचालित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आज शुक्रवार को जस्ट राइट चिल्ड्रन एवं समर्पण सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के तहत सुबह 11 बजे तहसील मुख्यालय से जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। रैली तहसील मुख्यालय से प्रारंभ होकर नुमाईशखेत तक पहुंचेगी। वहीं, अभियान के प्रति जनसामान्य को जागरूक करने तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के उन्मूलन का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शाम 4 बजे मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा। यह जुलूस भी तहसील मुख्यालय से प्रारंभ होकर नुमाईशखेत तक आयोजित होगा। आयोजकों ने आमजन से दोनों कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर सहभागिता करने की अपील की है, ताकि बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प जनआंदोलन का रूप ले सके

'ढाई आखर' पत्र लेखन प्रतियोगिता की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 31 दिसंबर तक भेज सकेंगे प्रविष्टियां

के.के.पी संवाददाता। डाक विभाग की ओर से वर्ष 2026-27 के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय स्तर की 'ढाई आखर' पत्र लेखन प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी गई है। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 31 दिसंबर कर दी गई है।

इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय एक चिट्ठी धरती मां के नाम - प्रकृति की रक्षा, मेरा वादा रखा गया है। प्रतियोगिता में 18 वर्ष तक और 18 वर्ष से अधिक आयु के दो वर्ग बनाए गए हैं। प्रतिभागी हिंदी, अंग्रेजी अथवा स्थानीय भाषा में हस्तलिखित पत्र भेज सकते हैं। अंतर्देशीय पत्र में अधिकतम 500 शब्द तथा लिफाफे में ए-4 आकार के कागज पर अधिकतम 1000 शब्दों की सीमा निर्धारित की गई है। प्रतियोगिता के तहत उत्तराखंड परिमंडल स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः 25 हजार, 10 हजार और पांच हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार 50 हजार, द्वितीय 25 हजार और तृतीय पुरस्कार 10 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। अधीक्षक डाकघर, अल्मोड़ा मंडल ने विद्यार्थियों, युवाओं, शिक्षकों और आम नागरिकों से प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करने की अपील की है।

विधानसभा चुनाव की तैयारी : मतदाताओं को ईवीएम-वीवीपैट की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान शुरू

के.के.पी संवाददाता। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देने, ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी शंकाओं का समाधान करने के उद्देश्य से जनपद में व्यापक जन-जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। अपर जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने जनपद के सभी मतदाताओं से अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक मतदाता का जागरूक होना और मतदान प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। उन्होंने मतदाताओं से इस अभियान के माध्यम से ईवीएम एवं वीवीपैट की कार्यप्रणाली को करीब से जानने का आग्रह किया। अभियान के तहत ईवीएम एवं वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) पूरी होने के बाद मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन के लिए 41 बैलेट यूनिट, 41 कंट्रोल यूनिट तथा 41 वीवीपैट मशीनें निकाली गई हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इन मशीनों की सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई है। साथ ही, निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार इन्हें अलग

बिंदुखत्ता को फिर मिली निराशा, कैबिनेट में नहीं हुआ फैसला; बापूग्राम के निर्णय को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रम

मुख्यमंत्री ने 23 नवंबर को दिया था 27 नवंबर की बैठक में निर्णय का भरोसा, लेकिन बिंदुखत्ता का कैबिनेट की सूची में नाम तक नहीं

के.के.पी संवाददाता

लालकुआं। बिंदुखत्ता को राजस्व गांव की अधिसूचना मिलने की वर्षों पुरानी उम्मीद एक बार फिर अधूरी रह गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार 23 नवंबर को बिंदुखत्ता पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आंदोलनकारियों से मुलाकात कर उनकी मांगों को सुना और बिंदुखत्ता से जुड़े महत्वपूर्ण विषय को 27 नवंबर की उच्चस्तरीय बैठक में रखने तथा निर्णय लेने का आश्वासन दिया था।

मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद क्षेत्रवासियों को उम्मीद थी कि शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में बिंदुखत्ता के भविष्य को लेकर कोई ठोस निर्णय सामने आएगा। लेकिन बैठक के बाद जारी 23 फैसलों की सूची में बिंदुखत्ता का नाम तक शामिल नहीं मिला। इससे क्षेत्रवासियों को एक बार फिर



निराशा हाथ लगी है। लंबे समय से बिंदुखत्ता के लोग राजस्व गांव की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद इस बार लोगों को उम्मीद थी कि उनकी वर्षों पुरानी समस्या के समाधान की दिशा में सरकार कदम उठाएगी, लेकिन कैबिनेट बैठक में कोई निर्णय नहीं होने से अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बिंदुखत्ता को राजस्व गांव की अधिसूचना कब मिलेगी?

इधर, सोशल मीडिया पर ऋषिकेश के बापूग्राम की 594.90 एकड़ वन भूमि को डीनोटिफाई करने के प्रस्ताव पर मिली सैद्धांतिक मंजूरी को बिंदुखत्ता से जोड़कर प्रचारित किया जा रहा है। जबकि कैबिनेट का यह फैसला केवल बापूग्राम के लिए है, बिंदुखत्ता के लिए ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है।

क्षेत्रवासी जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप उनकी वर्षों पुरानी मांग पर ठोस निर्णय आखिर कब लिया जाएगा।

जिलाधिकारी ने तहसील कार्यालय लक्सर में बनाए गए स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण

- आमजनमानस की जानकारी एवं डेमो के लिए लक्सर तहसील परिसर में रखी गई ईवीएम-वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा
- आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराना प्राथमिकता
- स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था एवं सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली का भी किया निरीक्षण

के.के.पी संवाददाता

हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने तहसील कार्यालय लक्सर में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर वहां की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आमजनमानस को ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों के प्रति जागरूक करने तथा उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी एवं डेमो के उद्देश्य से तहसील परिसर में रखी गई ईवीएम-वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया।

जिलाधिकारी ने स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्थाओं, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी एवं अन्य सुरक्षा इंतजामों का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूरी गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं निर्विघ्न



रूप से संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दायित्वों का गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन सुनिश्चित करें।

इस दौरान उपजिलाधिकारी लक्सर अनिल कुमार शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी, कर्मचारी एवं आमजन उपस्थित रहे।

मानव सेवा को सर्वोच्च मानकर कसार जन सेवा समिति ने गरीब परिवारों को बांटे कंबल-स्वेटर



के.के.पी संवाददाता

अल्मोड़ा। कसार जन सेवा समिति नरसिंहबाड़ी द्वारा मानव सेवा को सर्वोच्च सेवा की भावना को सर्वोपरि मानते हुए ठंड के मौसम में गरीब परिवारों को कंबल, स्वेटर का वितरण किया गया। इस अवसर पर नगर क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार की महिलाओं को आमंत्रित कर कसार जन सेवा समिति नरसिंहबाड़ी कार्यालय में एक समारोह में स्वेटर, कंबल इत्यादि का वितरण किया गया। इस अवसर पर एक दर्जन से अधिक गरीब परिवार की महिलाओं को कंबल व स्वेटरों का वितरण किया गया।इस अवसर पर कसार जन सेवा समिति की अध्यक्ष गंगा पाण्डे, समिति की उपाध्यक्ष मुक्ता जुकारिया, कोषाध्यक्ष सरिता कपिल तथा समिति के सचिव ज्योर्तिमय कपिल के अलावा रेखा शर्मा, कमला राठौर, लता काण्डपाल सहित अनेक महिलाएं उपस्थित थीं।समिति अध्यक्ष गंगा पाण्डे ने कहा कि प्रतिवर्ष यह समिति इसी तरह से मानव सेवा कार्य करती रहेगी तथा समाज के वंचित असहाय परिवारों को सहारा देने सहित हर सम्भव मानव धर्म सेवा कार्य करती रहेगी।

'सुरक्षित बचपन अभियान' के दूसरे चरण में जनपद के शिक्षकों को दी गई बाल संरक्षण कानूनों की जानकारी

सिविल जज रश्मि गोयल ने शिक्षकों की भूमिका पर डाला प्रकाश, पॉक्सो एक्ट के प्रावधान विस्तार से बताए गए

के.के.पी संवाददाता

चम्पावत। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार संचालित विशेष जागरूकता अभियान 'सुरक्षित बचपन अभियान' के दूसरे चरण के तहत आज 27 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को जिला न्यायालय सभागार कक्ष में जनपद के चयनित विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन), चम्पावत रश्मि गोयल ने अभियान के उद्देश्यों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और बाल



संरक्षण से जुड़े अन्य कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।

इसके अतिरिक्त सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत ने कार्यक्रम के समापन तक शिक्षकों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी।

उन्होंने बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न की पहचान करने के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही ऐसी घटनाओं की जानकारी मिलने पर की जाने वाली आवश्यक कानूनी और विभागीय कार्रवाई के बारे में भी बताया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन निर्धारित विशेष मॉड्यूल के अनुरूप किया गया। उपस्थित शिक्षकों को मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी जागरूक किया गया। शिक्षकों से अपेक्षा की गई कि वे प्रशिक्षण में मिली जानकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों, उनके अभिभावकों और अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बच्चों के लिए सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

चम्पावत के चारों विकासखंडों में बनेंगे 41 मोटर मार्ग, पीएमजीएसवाई-4 में 531.62 करोड़ रुपये की स्वीकृति

388 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कें बनेंगी, चम्पावत में 17, लोहाघाट में 4, बाराकोट में 7 और पाटी में 13 मार्ग

के.के.पी संवाददाता

चम्पावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-4) के अंतर्गत जनपद चम्पावत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल 41 मोटर मार्गों के निर्माण की स्वीकृति दी है। इन मार्गों की कुल लंबाई 388.305 किलोमीटर और कुल लागत 53,162.041 लाख रुपये (लगभग 531.62 करोड़ रुपये) है। इनके निर्माण से सुदूरवर्ती और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी।

अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई, चम्पावत बीरेंद्र सिंह ने बताया कि चम्पावत विकासखंड के 17 मोटर मार्ग स्वीकृत हुए हैं। ये इस प्रकार हैं:

चम्पावत विकासखंड (कुल 17 मार्ग)

* मंच से बकोड़ाः 22.300 किमी, 3,470.93 लाख
* ज्याड़ा-रौकुंवर से भंडारबोराः 13.650 किमी, 2,302.01 लाख
* सतकुला से रुइयाः 9.630 किमी, 1,461.22 लाख
* लड़ाबोरा से कंवरसिंगः 6.900 किमी, 1,110.46 लाख
* दियूरी-बगेरी से फुरकियाझालाः 15.500 किमी, 2,641.67 लाख
* धूनाघाट रीठासाहिब मोटर मार्ग से पिनानाः 9.750 किमी, 1,472.20 लाख
* एनएच-09 किमी-100 से कोट अमोड़ी-जौरकाः 7.000 किमी, 1,092.02 लाख
* चतुरकोट से तल्ला कफल्टाः 6.150 किमी, 941.98 लाख
* आमनी से रायलः 9.120 किमी, 1,349.65 लाख
* चूका-खरायत-कोट केंद्री-खिरद्वारी से गंगसीरः 22.450 किमी, 2,893.43 लाख
* सल्ली-कुकड़ैनी-आमखेतः 14.000 किमी, 2,196.56 लाख
* ललुवापानी बनलेख मोटर मार्ग से मोराड़ीः 5.200 किमी, 858.40 लाख
* गुरेली-कालूखान से मैरोलीः 9.475 किमी, 1,446.27 लाख
* सुकनी से बुरम-कठौलः 19.500 किमी, 2,971.20 लाख
* मंच-दुबडजैनल मोटर मार्ग से गोरखोलीः 8.100 किमी, 1,216.11 लाख
* सिप्टी-न्याड़ी मोटर मार्ग से पड़ूंगा-डुगरा-रीठाः 12.380 किमी, 1,892.03 लाख
* टनकपुर-जौलजीबी से सोराई-हरतोलाः 20.150 किमी, 3,063.77 लाख

चम्पावत विकासखंड में कुल लंबाई 211.26 किमी और कुल लागत लगभग 323.80 करोड़ रुपये (32,379.91 लाख रुपये) है।

अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई, लोहाघाट बीसी नैनवाल ने बताया कि लोहाघाट, बाराकोट और पाटी विकासखंडों के 24 मोटर मार्ग स्वीकृत हुए हैं। इनमें लोहाघाट के 4, बाराकोट के 7 और पाटी के 13 मार्ग शामिल हैं।

लोहाघाट विकासखंड (कुल 4 मार्ग)

* रौशाल-डुंगराबोरा मोटर मार्ग से मडुवा-रेकुवाः 15.200 किमी, 2,096.44 लाख
* चमदेवल जाख मोटर मार्ग से चामा-सागरः 4.400 किमी, 654.78 लाख
* रौशाल-डुंगराबोरा मोटर मार्ग से कयाल-भोजिनीः 5.850 किमी, 841.17 लाख
* किमतोली रौशाल मोटर मार्ग से डुंगरीः 8.800 किमी, 1,301.93 लाख

लोहाघाट विकासखंड में कुल लंबाई 34.250 किमी और कुल लागत लगभग 48.94 करोड़ रुपये (4,894.32 लाख रुपये) है।

बाराकोट विकासखंड (कुल 7 मार्ग)

* एसएच से गल्लागांवः 4.150 किमी, 347.06 लाख
* डायरतोली से बांस बेट्टाः 9.850 किमी, 832.17 लाख
* सेरीबैंड से अधखंडीः 1.630 किमी, 146.52 लाख
* ब्लॉक ऑफिस बाराकोट से फरतोलाः 4.000 किमी, 313.44 लाख
* एनएच-125 से गुवेनाराः 3.325 किमी, 261.92 लाख
* पातल से शील बर्यूलीः 22.400 किमी, 2,460.88 लाख
* तरीगांव से नौमानाः 1.880 किमी, 214.30 लाख

बाराकोट विकासखंड में कुल लंबाई 47.235 किमी और कुल लागत लगभग 45.76 करोड़ रुपये (4,576.29 लाख रुपये) है।

पाटी विकासखंड (कुल 13 मार्ग)

* बलकाश बैंड से बड़ैत कोटाः 2.200 किमी, 238.93 लाख
* बतुलीया प्याली से भनार (गूम): 7.250 किमी, 717.03 लाख
* गरसाड़ी से बीसा उलारी बिगराकोटः 4.325 किमी, 434.11 लाख
* रमक से खीरकुड़ाः 8.800 किमी, 722.97 लाख
* रमक कोटा से मंगललेखः 9.420 किमी, 919.04 लाख
* सिल्लिंग से जनकांडेः 2.650 किमी, 221.513 लाख
* धूनाघाट से बर्मतोलाः 4.700 किमी, 359.52 लाख
* बिनवालगांव से गोलडाण्डाः 15.090 किमी, 1,647.10 लाख
* बरनी से चौरासौंः 10.500 किमी, 1,528.32 लाख
* सिल्लिंग से त्यारसौंः 3.200 किमी, 463.89 लाख
* छंदा से जमर जमरेड़ीः 6.800 किमी, 1,027.69 लाख
* मूलाकोट से मझ्याप नेलोरीः 13.780 किमी, 2,040.99 लाख
* शिवमंदिर गरसाड़ी से पारस रखोलीः 6.850 किमी, 990.42 लाख

पाटी विकासखंड में कुल लंबाई 95.565 किमी और कुल लागत लगभग 113.12 करोड़ रुपये (11,311.523 लाख रुपये) है।

इन सड़कों के बनने से ग्रामीण संपर्क बेहतर होने और सुदूरवर्ती गांवों के लोगों को आवागमन की कठिनाइयों से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही क्षेत्र में पर्यटन और स्वरोजगार के नए अवसर बनने की भी संभावना जताई गई है।

मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से उत्तराखंड के उद्यमियों एवं निर्यातकों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने की पहल

राज्य स्तरीय कार्यशाला में निर्यात संवर्धन, सीमा शुल्क रियायतों और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध अवसरों पर हुआ मंथन

प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों की निर्यात क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर

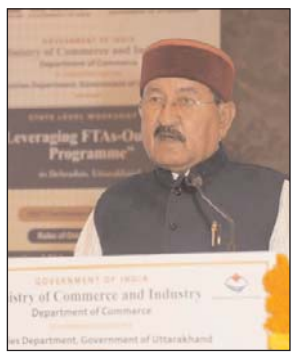



के.के.पी संवाददाता

देहरादून। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय प्राधिकरण, दिल्ली तथा उत्तराखंड सरकार के उद्योग निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को होटल हयात सेंट्रिक, देहरादून में 'मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना' (Leveraging Free Trade Agreements-FTAs) विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), उद्यमियों और निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों के प्रावधानों, उपलब्ध अवसरों एवं निर्यात संभावनाओं से अवगत कराते हुए वैश्विक बाजारों से जोड़ना रहा।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि यह कार्यशाला प्रदेश के उद्यमियों, निर्यातकों और विशेष रूप से एमएसएमई इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने तथा उनकी निर्यात क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उत्पादों को शून्य अथवा रियायती सीमा शुल्क पर विदेशी बाजारों में प्रवेश के नए अवसर मिलते हैं। श्री चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड का निर्यात वर्ष 2017-18 में 10,836 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 13,802 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें औषधि निर्माण, इंजीनियरिंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक एवं हर्बल उत्पादों तथा हस्तशिल्प क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि 'इन्वेस्ट उत्तराखंड' सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से विगत तीन वर्षों में 6,932 परियोजनाओं के लिए 70,397 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 तथा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स-2026 में भी उत्तराखंड ने अपनी श्रेणी में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पौड़ी, चमोली एवं अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। हरिद्वार में 194 करोड़ रुपये की लागत से बहुमंजिला औद्योगिक परिसर (फ्लैटेड फैक्ट्री) स्थापित किया जा रहा है, जबकि सेलाकुई एवं पंतनगर में भी ऐसे परिसर प्रस्तावित हैं।

दोहरे नाम वाले मतदाताओं की DSE के माध्यम से होगी जांच

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की राजनैतिक दलों के साथ बैठक

मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि को ठीक करने के लिए निरंतर चलेगा अभियान



के.के.पी संवाददाता

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में शुक्रवार को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (SSR) के तहत प्रदेश में चल रहे अभियान की राजनैतिक दलों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों को अवगत कराया कि स्स्क्र के तहत मतदाताओं की किसी भी प्रकार की त्रुटी को ठीक करने के लिए दावे / आपत्तियों को दर्ज करने की अवधि तक निरंतर अभियान चलता रहेगा। उन्होंने राजनैतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि मतदाताओं के नाम आदि में त्रुटियों को ठीक करने के लिए बीएलए के माध्यम से भी फार्म-8 भरे जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों को यह भी अवगत कराया कि प्रदेश में ऐसे मतदाता जिनकी दो स्थानों पर नाम दर्ज है उन्हें डीएसई (डुप्लीकेट सिमिलर एंट्री) मॉड्यूल के माध्यम से चिन्हित कर नियमानुसार जाँच कर निस्तारित किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों को जानकारी देते हुए बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत 12 नवंबर 2026 से अब तक फार्म-6 लगभग 50 हजार, फार्म-7 लगभग 8000 एवं 43 हजार फार्म-8 प्राप्त हो चुके हैं। आयोग द्वारा जारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के कार्यक्रमानुसार 12 नवंबर 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय निर्धारित किया गया है।

सिल्क्यारा रेस्क्यू अभियान को याद कर भावुक हुए मा0 मुख्यमंत्री

के.के.पी संवाददाता

देहरादून। सिल्क्यारा रेस्क्यू अभियान को याद करता हूं तो आज भी मन भावुक हो जाता है। 12 नवंबर 2023 का वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा था और उसी दिन उत्तरकाशी से यह खबर आई कि सिल्क्यारा-बड़कोट निर्माणाधीन सुरंग में 41 श्रमिक फंस गए हैं। जैसे-जैसे घटना की गंभीरता सामने आई, हमारी सबसे बड़ी चिंता उन 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की थी।

उस समय मेरे मन में केवल एक बात थी कि सुरंग के अंदर फंसे प्रत्येक श्रमिक को सुरक्षित बाहर लाना है। उनके परिवारों की चिंता, उनकी आंखों में अपने परिजनों को सुरक्षित देखने की उम्मीद और सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों का भरोसाकृइन सबने हमारे संकल्प को और मजबूत किया। मैंने श्रमिकों के परिजनों से कहा था कि हम पूरी ताकत से प्रयास करेंगे और उनके अपनों को सुरक्षित वापस लाएंगे। उनके परिवारों के साथ बिताया गया हर क्षण आज भी मेरी स्मृतियों में है। एक मुख्यमंत्री के रूप में वह केवल एक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत संकल्प भी था। हर बैठक में, हर समीक्षा में और हर निर्णय के दौरान मेरे सामने उन 41 श्रमिकों के चेहरे और उनके परिवारों की उम्मीदें रहती थीं।

सिल्क्यारा में परिस्थितियां लगातार चुनौतीपूर्ण थीं। कई बार ऐसा लगता था कि अब हम सफलता के बहुत करीब पहुंच गए हैं। लगता था कि आज श्रमिकों को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन तभी कोई नई रुकावट सामने आ जाती थी। कभी मलबा रास्ता रोक देता था, कभी चट्टानों के कारण मशीनों के सामने कठिनाई आती थी और कभी हमें अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ता था। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग के दौरान आई बाधाओं ने चुनौती को और कठिन बना दिया था। लेकिन हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक रास्ते में रुकावट आई तो दूसरे विकल्प पर काम शुरू किया गया। क्षैतिज ड्रिलिंग के साथ वर्टिकल ड्रिलिंग, वैकल्पिक मार्ग और अन्य तकनीकी विकल्पों पर एक साथ काम किया गया। देश के विशेषज्ञों के साथ अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहायता ली गई। हर एजेंसी, हर विशेषज्ञ और हर व्यक्ति का एक ही लक्ष्य थाकृमलबे के उस पार फंसी 41 जिंदगियों तक पहुंचना।

इन सबके बीच सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों का साहस हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा था। 17 दिन तक इतनी कठिन परिस्थितियों में रहकर भी उन्होंने जिस धैर्य और हिम्मत का परिचय दिया, उसने बाहर काम कर रही पूरी टीम का हौसला बढ़ाया। जब उनकी आवाज हम तक पहुंचती थी और हमें पता चलता था कि उनका मनोबल बना हुआ है, तो हमें भी विश्वास मिलता था कि हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार पूरे अभियान की जानकारी लेते रहे। उनका स्पष्ट संदेश था कि श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए हरसंभव प्रयास किया जाए। केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों, राज्य की एजेंसियों, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, प्रशासन, तकनीकी विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर काम किया। यह वास्तव में पूरे देश के सामूहिक प्रयास का अभियान था।

मुझे आज भी 28 नवंबर 2023 का वह क्षण याद है, जब पहला श्रमिक सुरंग से बाहर आया।

90 साल से महिला शिक्षा की अलख जगा रहा संस्थान, 'अनुभूति' में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा





के.के.पी संवाददाता

हरिद्वार। सतीकुंड कनखल स्थित श्रीमती शकुंतला शास्त्री स्मारक महिला इंटर कॉलेज में शुक्रवार को वार्षिकोत्सव 'अनुभूति' धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। 90 वर्षों से महिला शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए संस्था के वार्षिकोत्सव में छात्राओं ने नृत्य, नृत्य नाटिका और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, उत्तराखंड की विरासत, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सरोकारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक डॉ. अशोक शास्त्री, संरक्षिका डॉ. वीणा शास्त्री, एमसीएस बाल विद्यापीठ सतीकुंड की निदेशिका डॉ. विशाखा कुमार, प्रधानाचार्य रेखा पुरोहित और निर्देशिका शशि प्रभा वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विद्यालय की वार्षिक पत्रिका 'मीमांसा' के वर्ष 2026-27 के संस्करण का विमोचन भी किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत छात्राओं ने 'सृष्टि का स्पंदन' नृत्य से की। इसके बाद 'ग्लोरियस एंड प्रॉस्परस इंडिया' के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को दर्शाया गया।

रविंद्र संगीत पर आधारित नृत्य प्रस्तुति ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। भारत रत्न एवं पद्म श्री से सम्मानित डॉ. भूपेंद्र हजारिका और जुबीन गर्ग को समर्पित 'अमर सुरों का महासंगम' ने भावुक कर दिया।

प्रथम आपदा प्रबंधन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की चार महत्वपूर्ण घोषणाएं

आवासीय भवनों में दुर्घटनावश आग लगने की घटनाओं को माना जाएगा आपदा, प्रभावितों को एसडीआरएफ के मानकों के अनुरूप मिलेगी राहत राशि

आपदाओं एवं सड़क दुर्घटनाओं के दौरान नि :स्वार्थ भाव से राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग करने वाले लोगों को किया जाएगा पुरस्कृत

सिलक्यारा बचाव अभियान साहस, धैर्य और बेहतर समन्वय की ऐतिहासिक मिसाल : मुख्यमंत्री





के.के.पी संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय, देहरादून में प्रथम आपदा प्रबंधन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा जनसहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भूतपूर्व सैनिकों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, पुलिस तथा अन्य वर्दीधारी सेवाओं के सेवानिवृत्त कार्मिकों को आपदा से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनके सहयोग से आम जनमानस को आपदाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्रथम चरण में अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रति एक हजार विद्यार्थियों पर एक शिक्षक को राज्य सरकार द्वारा आपदा मित्र अथवा आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इनके माध्यम से छात्र-छात्राओं को आपदाओं के प्रति निरंतर जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आवासीय भवनों में किसी भी प्रकार की दुर्घटना के कारण आग लगने की घटना को आपदा के रूप में स्वीकार किया जाएगा तथा ऐसे अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के मानकों के अनुरूप राहत राशि प्रदान की जाएगी। आपदाओं एवं सड़क दुर्घटनाओं के दौरान निःस्वार्थ भाव से राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस असवर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) पुस्तिका एवं उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) 2026-27 का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आपदा प्रबंधन हमारे लिए निरंतर एक चुनौतीपूर्ण विषय है। प्रदेश को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपदाओं के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के साथ ही प्रत्येक स्तर पर पूर्व तैयारियों को मजबूत करना आवश्यक है। आपदा प्रबंधन से विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को भी जोड़ा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपदा की सूचना मिलते ही पूरा तंत्र सक्रिय हो और प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द राहत एवं सहायता पहुंचे। कठिन परिस्थितियों में आपदा प्रभावितों के बीच जाकर उनके साथ खड़े रहना आवश्यक है। पिछले दो-तीन वर्षों में प्रदेश ने अनेक आपदाओं का सामना किया है।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की 32.58 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

के.के.पी संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाढ़ सुरक्षा, खेल अवस्थापना, सौर ऊर्जा, पर्यटन विकास, मंदिरों के सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों के लिए 32.58 करोड़ से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने जनपद चमोली के विकासखंड थराली में कुलसारी बहुउद्देशीय मैदान को पिंडर नदी के कटाव से बचाने के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु 491.98 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोलापार, हल्द्वानी में एकीकृत खेल अवस्थापना विकास परियोजना के अंतर्गत 100 लाख के निर्माण कार्य के लिए पेयजल निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित हुए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में शासकीय भवनों (3042 स्थानों) पर 17 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए 40.67 करोड़ के सापेक्ष द्वितीय किश्त में 16.268 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय परिसर की द्वितीय यूनिट में परीक्षा हॉल, गेस्ट हाउस के सम्मुख लॉन, आंतरिक सड़क निर्माण एवं फर्नीशिंग आदि कार्यों के लिए आगणित 309.77 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त में 123.908 लाख अवमुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत विकासखंड विण स्थित ग्रामसभा उपरतोला में आंतरिक मार्ग निर्माण हेतु 84.94 लाख तथा डीडीहाट विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत द्योगली में सीसी मार्ग, खड़ंजा एवं सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 99.69 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में 59.814 लाख की धनराशि जारी करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा एक जनपद एक नदी योजना के अंतर्गत जनपद बागेश्वर की गरुड़ गंगा की कार्य योजना 1120.16 लाख के सापेक्ष प्रथम चरण में 316.58 लाख की धनराशि अवमुक्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में 50 हैंडपंप स्थापित करने के लिए 42.98 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद टिहरी के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विकासखंड कीर्तिनगर स्थित चौकी महादेव शिवालय के सौंदर्यीकरण किये जाने हेतु 67.87 लाख की स्वीकृति प्रदान कर प्रथम किश्त में 40.722 लाख तथा क्षेत्रपाल देवता, धौड़ांगी बडियारगढ़ एवं हिण्डोलाखाल के ढुंगरियाल कांडा स्थित चामुंडा देवी मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए 100.67 लाख की स्वीकृति प्रदान कर प्रथम किश्त में 80.294 लाख की धनराशि जारी करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अग्निवीर भर्ती रैली के चौथे दिन चम्पावत जिले की तीन तहसीलों के 850 से अधिक युवा पहुंचे, करीब 700 दौड़ में सफल

अपने ही जिले में भर्ती का अवसर मिलने से अभ्यर्थियों में दिखा उत्साह



के.के.पी संवाददाता

चम्पावत। बनबसा सैन्य स्टेशन में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के चौथे दिन गुरुवार को चम्पावत जिले की चम्पावत, पाटी और पूर्णागिरि तहसीलों के अभ्यर्थियों ने भाग लिया। प्रारंभिक दस्तावेज जांच के बाद 850 से अधिक युवाओं को रैली स्थल में प्रवेश दिया गया। अपने ही जिले में भर्ती का अवसर मिलने से अभ्यर्थियों में उत्साह दिखा।

अभ्यर्थियों की दौड़ नौ बैचों में कराई गई, जिसमें करीब 700 अभ्यर्थी सफल रहे। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन और शारीरिक व चिकित्सकीय परीक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। पिछले दिनों दौड़ में सफल रहे अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण भी जारी है। रैली का आयोजन जोनल भर्ती कार्यालय (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड) के अधीन सेना भर्ती कार्यालय, पिथौरागढ़ की ओर से किया जा रहा है। भर्ती निदेशक कर्नल अमोल दबड़घाव की देखरेख में सेना के अधिकारियों और जवानों ने प्रवेश, दस्तावेज जांच और दौड़ की व्यवस्थाएं संभालीं।

शुक्रवार, 27 नवंबर को लोहाघाट और बाराकोट तहसीलों के अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) अभ्यर्थी दौड़ में भाग लेंगे। इसी दिन चम्पावत और पिथौरागढ़ जिलों के अग्निवीर टेक्निकल और ट्रेड्समैन श्रेणी के अभ्यर्थी भी दौड़ में शामिल होंगे।

लोहाघाट नगर पालिका ने मेधावी छात्र-छात्राओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल युवाओं और स्वच्छता में सहयोगियों को किया सम्मानित

जिलाधिकारी मनीष कुमार रहे मौजूद, बच्चों और महिलाओं की खेल प्रतियोगिताएं भी हुई



के.के.पी संवाददाता

लोहाघाट। नगर पालिका के तत्वावधान में आज नगर के मेधावी छात्र-छात्राओं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल रहे युवाओं, महिलाओं और नगर क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग देने वाले लोगों को सार्वजनिक तौर पर पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए जो कार्यक्रम संचालित कर रही है, उसी कड़ी में नगर पालिका ने यह विशेष प्रयास किया है, जिससे नगर की प्रतिभाओं के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्र के सभी विद्यालयों में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर शुभकामनाएं दीं। साथ ही लोअर पीसीएस में सफल रहे अनिमेष पुनेठा, सेना में लेफ्टिनेंट बने महल खर्कवाल, वैज्ञानिक पद पर चयनित आस्तिक पांडे, केंद्रीय गृह मंत्रालय में एएसओ पद पर चयनित गौरव राय, उनके भाई एवं सेना में लेफ्टिनेंट बने मयंक राय, पूर्व कमांडो एवं निशुल्क रूप से युवाओं को फौज और पुलिस के लिए तैयार कर रहे मनोज करायत तथा जीएसटी में एसआई पद पर चयनित प्रवीण धौनी को भी सम्मानित किया गया।

इसके अलावा स्वच्छता अभियान में सहयोग के लिए कचहरी वार्ड में अजय उप्रेती और भुवन धौनी, खड़ी बाजार में टीका देव खर्कवाल, स्टेशन बाजार में गिरीश बगोली और उमेश उपाध्याय तथा ठाड़ा दूंगा क्षेत्र में नीलांबर पांडे को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

इससे पूर्व जिलाधिकारी के पहुंचने पर नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश चंद्र पांडे, दर्जा राज्य मंत्री सुभाष बगौली और निर्मल मेहरा सहित अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर बच्चों की पेंटिंग, फैंसी ड्रेस, क्विज और काव्य पाठ तथा महिलाओं की घड़ा फोड़, रस्साकशी, आना-किस्सा, बाल्टी बॉल और कुर्सी दौड़ प्रतियोगिताएं हुईं, जिन्हें देखने के लिए पूरा मैदान भरा हुआ था।

अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने सभी लोगों का स्वागत और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नगर क्षेत्र को साफ-सुथरा बनाए रखने में लोगों का उल्लेखनीय सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और अनेक कार्यक्रम किए जाएंगे। इस मौके पर नगर पालिका के सभी सभासद भी मौजूद रहे और आयोजन में सहयोग दिया।

संपादकीय

मतदाता सूची विवाद राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना?

- एसआईआर रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग तेज

संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को देशभर में चुनावी पारदर्शिता और मताधिकार की रक्षा को लेकर जिस तरह विरोध प्रदर्शनों का आयोजन हुआ, उसने भारतीय राजनीति में एक नए तूफान को जन्म दिया है। अब तक विपक्षी दल और विभिन्न सामाजिक संगठन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग कर रहे थे। अब इस आंदोलन में एक नई और बड़ी मांग जुड़ गई है। यह मांग है, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को तत्काल रद्द करने और पुरानी मतदाता सूची को बहाल करने की है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने संविधान दिवस पर संविधान बचाओ और वोट चोरी के आरोपों के साथ देशव्यापी प्रदर्शन आयोजित किए। दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में सफल विरोध कार्यक्रम हुए। आंदोलन में सामाजिक संगठनों, युवाओं और नागरिक अधिकार समूहों की भागीदारी बड़ी संख्या मे देखने को मिली। विपक्ष का आरोप है, मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया से बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदान सूची से अलग कर दिए गए हैं, जिसके कारण चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। 13 करोड़ से अधिक नाम हटने का विवाद अब चरम स्तर पर पहुंच गया है। एसआईआर को लेकर सबसे बड़ा सवाल मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर है। सितंबर 2026 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रारूप मतदाता सूचियों से लगभग 13.37 करोड़ नाम कम हुए हैं। यह संख्या पहले से दर्ज मतदाताओं का करीब 14.1 प्रतिशत है। हालांकि, यह कहना मुश्किल है, प्रारूप सूची से हटाए गए सभी नाम स्थायी रूप से काटे गए हैं। सभी वास्तविक मतदाता थे? ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। फिर भी बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो मतदाता हटाए गए थे उनकी संख्या बड़ी मात्रा में है, जिसके कारण चुनाव आयोग निशाने पर है। इतने बड़े पैमाने पर नामों का कम होना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

विपक्ष की मांग है, 2024 अथवा 2025 की पूर्ववर्ती मतदाता सूची को आधार बनाकर नए सिरे से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए। जिन लोगों के नाम गलत तरीके से हटे हैं, उन्हें बिना जटिल दस्तावेजी प्रक्रिया के मतदाता सूची में वापस शामिल किया जाए। यह काम बीएलओ और रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में हो। पिछले कुछ महीनों में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कई गंभीर रिपोर्टें सामने आई हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक विस्तृत पड़ताल में दावा किया गया था, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ काम कर रहे दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों ने पिछले दस महीनों में 14 बार निर्णयों पर आपत्ति दर्ज कराई थी। इनमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। यह मामला आयोग के आंतरिक निर्णयों और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। इसके अलावा, एसआईआर के दौरान फॉर्म-6 में कथित बदलाव और आयोग के निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आयोग ने अपने जवाब में निर्णयों को सर्वसम्मति से लिया गया बताया है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं। अब विपक्ष आयोग से आंतरिक फाइलों, निर्णयों और संबंधित रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है, जो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर रहा है। मतदान के आंकड़ों और ईवीएम से संबंधित विसंगतियों को लेकर भी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। प्रमाणों के साथ गड़बड़ियों को उजागर किया गया है। अलग-अलग फॉर्म में दर्ज मतदाताओं और मतदान के आंकड़ों का अंतर चुनावी धांधली से जोड़ा गया है। इन मामलों में बूथवार दस्तावेजों और आधिकारिक जांच के आधार पर ही निष्कर्ष निकला गया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। एसआईआर के मामले की सुनवाई लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। 17 नवंबर की सुनवाई में न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को निर्वाचन आयोग के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए दस दिन का समय दिया है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की ओर से आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर के लिए निर्धारित है। दिल्ली में एसआईआर से बाहर हुए मतदाताओं को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से प्रगति रिपोर्ट मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट का फूड कंपनियों पर बड़ा प्रहार

एडवोकेट किशन

हर पैकेट पर अलग-अलग लाल चेतावनी के हेक्सागन से खुलेगी पोल! निर्माता से लेकर होलसेलर और रिटेलर नहीं बच सकेंगे जिम्मेदारी से जवाबदेही तय!खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धाराएं 23,24,26, 27 और 28 बनाम फूड कंपनियों की जवाबदेही ! लेबलिंग विनियम 2020 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप, संविधान के अनुच्छेद 21 और 47 की भी अग्निपरीक्षा !बच्चों की पोषण साक्षरता और यमुना प्रदूषण पर भी अदालत सख्त समग्र व्यापक महा- विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट का फूड कंपनियों पर महाप्रहार, हर पैकेट पर अलग-अलग लाल चेतावनी के हेक्सागन से खुलेगी पोल! निर्माता से दुकानदार तक तय होगी जवाबदेही, बच्चों की सेहत पर भी अदालत का बड़ा फैसला!

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश, एफ़ एसएसएआई को लाल हेक्सागन चेतावनी के नए नियम बनाने का निर्देश!अब पैकेट पर छिपे नहीं रहेंगे चीनी,नमक और फैट के राज! लाल हेक्सागन बताएगा खाने का सच! जनता की सेहत से खिलवाड़ नहीं, निर्माता से लेकर होलसेलर और रिटेलर क़ी जवाबदेही होगी तय!

वैश्विक स्तरपर वर्तमान डिजिटल और आधुनिक उपभोक्तावादी युग में पैकेटबंद खाद्य पदार्थों का बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है।आलू केचिप्स,चॉकलेट केक बिस्किट,इंस्टेंट नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स से लेकर आटा चावल गेहूं,रवा,मैदा और खाद्य तेल तक लगभग हर वस्तु आकर्षक पैकेजिंग में उपलब्ध है। आम उपभोक्ता के मन में एक धारणा बन गई है कि खुला खाद्य पदार्थ अशुद्ध अथवा मिलावटी हो सकता है, जबकि कंपनी की सीलबंद पैकिंग वाला उत्पाद गुणवत्ता और सुरक्षा की गारंटी देता है।लेकिन यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है।पैकेटबंद होना अपने आप में सुरक्षित,पौष्टिक अथवा मिलावट मुक्त होने का प्रमाण नहीं है।पैकेजिंग उत्पाद को बाहरीसंदूषण से बचाने में मदद कर सकती है,लेकिन उसके अंदर मौजूद चीनी, नमक, संतृप्त वसा और अन्य पोषक तत्वों की अधिकता को समाप्त नहीं करती।यही वह बुनियादी सवाल है,जिसने अब भारत में खाद्य सुरक्षा उपभोक्ता अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य की बहस को राष्ट्रीय ही नहीं,अंतरराष्ट्रीय महत्व प्रदान कर दिया है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहूंगा क़ि 26 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट की माननीय दो जजों की की पीठ ने 3 एस एंड अवर हेल्थ सोसाइटी बनाम भारत संघ मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। यह जनहित याचिका पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर उपभोक्ताओं को आसानी से समझ आने वाली पोषण संबंधी चेतावनी देने से संबंधित है।अदालत ने केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग अर्थात पैकेट के सामने पोषण चेतावनी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के सामने की तरफ हाई शुगर, हाई फैट और हाई सॉल्ट के लिए अलग-अलग लाल चेतावनी लेबल लगाने के नियम तैयार करने का निर्देश दिया है।हर पोषक तत्व (शुगर,फैट,नमक) के लिए अलग लाल हेक्सागन (षटकोण) निशान होगा।तीनों की एक संयुक्त चेतावनी मान्य नहीं होगी।प्रत्येक हेक्सागन पैकेट के मुख्य डिस्प्ले पैनल का 4 से 5 प्रतिशत हिस्सा घेरेगा, जिस पर स्पष्ट फॉन्ट और संबंधित पोषक तत्व का चित्र होगा। केवल एडेड शुगर या फैट नहीं, बल्कि टोटल शुगर और सैचुरेटेड फैट की कुल मात्रा तथा वैज्ञानिक मानकों के आधार पर सीमा तय करनी होगी। कोर्ट ने नियम बनाने और आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई 10 सप्ताह बाद तय की है।

साथियों बात अगर हम पैकेटबंद खाद्य पदार्थों कीकानूनी जवाबदेही किसकी? निर्माता नहीं बच सकता,विक्रेता भी नहीं! इसको समझने की करेंतो,इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू खाद्य पदार्थों की जिम्मेदारी है। अक्सर देखने में आता है कि निर्माता अपनी जिम्मेदारी होलसेलर पर, होलसेलर रिटेलर पर और रिटेलर निर्माता पर डालने का प्रयास करता है। लेकिन भारतीय कानून में ऐसा करके कोई भी खाद्य कारोबारी स्वतः जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकता। इसके लिए संसद ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 बनाया है।इसकी धारा 23 पैकेजिंग एवं लेबलिंग,धारा 24 भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार,धारा 26 खाद्य कारोबार संचालक की जिम्मेदारी तथा धारा 27 निर्माता,पैकर, थोक विक्रेता वितरक और खुदरा विक्रेता की अलग- अलग जवाबदेही निर्धारित करती है।धारा 27 (1) के अनुसार खाद्य पदार्थ निर्धारित कानून, नियम और विनियमों के अनुरूप नहीं है तो निर्माता अथवा पैकर जिम्मेदार होगा।धारा 27(2) के तहत एक्सपायरी के बाद आपूर्ति, निर्माता के सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन करके भंडारण, असुरक्षित अथवा गलत लेबल वाले उत्पाद की आपूर्ति और निर्माता की पहचान नहीं बता पाने जैसी परिस्थितियों में होलसेलर एवं वितरक जिम्मेदार होंगे। इसी प्रकार धारा 27(3) के तहत एक्सपायरी के बाद बिक्री, अस्वच्छ परिस्थितियों में रखरखाव, गलत लेबलिंग निर्माता या वितरक की पहचान नहीं होना अथवा असुरक्षित होने की जानकारी के बावजूद बिक्री करने पर रिटेलर भी जवाबदेह होगा। अर्थात जवाबदेही उत्पाद की प्रकृति और संबंधित कारोबारी की भूमिका के आधार पर तय होगी, केवल पैकेट पर कंपनी का नाम देखकर नहीं।

साथियों, धारा 28 असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बाजार से वापसी अर्थात फूड रिकॉल का प्रावधान करती है।धारा 31 लाइसेंस और पंजीकरण, धारा 32 सुधारात्मकनोटिस धारा 38 खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां तथा धारा 40 उपभोक्ता द्वारा खाद्य पदार्थ का विश्लेषण करवाने का अधिकार प्रदान करती है। धारा 50 में निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप खाद्य पदार्थ न बेचने पर पांच लाख रुपये तक, धारा 51 में घटिया खाद्य पर पांच लाख रुपये तक,धारा 52 में गलत ब्रांडिंग पर तीन लाख रुपये तक और धारा 53 में भ्रामक विज्ञापन पर दस लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। असुरक्षित खाद्य के मामलों में धारा 59 के अंतर्गत परिस्थितियों और स्वास्थ्य को हुए नुकसान के अनुसार छह महीने से लेकर आजीवन कारावास तक का दंड तथा जुर्माने का प्रावधान है। धारा 63 बिना आवश्यक लाइसेंस कारोबार करने पर छह महीने तक कारावास और पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान करती है। धारा 65 उपभोक्ता को चोट या मृत्यु होने पर मुआवजे तथा धारा 66 कंपनी के अपराधों की जवाबदेही से संबंधित है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि पैकेटबंद उत्पाद में गड़बड़ी मिलने पर केवल निर्माता ही जिम्मेदार होगा अथवा केवल दुकानदार ही दोषी होगा। कानून प्रत्येक स्तर पर उसकी अपनी गलती, जानकारी,नियंत्रण और वैधानिक कर्तव्य के अनुसार सटीकता से जवाबदेही निर्धारित करता है।

साथियों बात अगर हम तीन अलग-अलग लाल षटकोणः एक चेतावनी नहीं,हर पोषक तत्व की अलग पहचान! को समझने की करें तो,सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्धारित वैज्ञानिक सीमा से अधिक चीनी, संतृप्त वसा अथवा नमक होने पर प्रत्येक के लिए अलग-अलग लाल रंग का छह कोनों वाला षटकोण अर्थात हेक्सागन चेतावनी चिह्न होना चाहिए। इनमें संबंधित चित्र और स्पष्ट शब्द होंगे हाई शुगर, हाई फैट और हाई सॉल्ट। यदि किसी उत्पाद में तीनों तत्व अधिक हैं तो तीन अलग-अलग चेतावनी चिह्न लगाने होंगे। एक संयुक्त चिह्न पर्याप्त नहीं होगा।प्रत्येक चेतावनी का आकार पैकेट के मुख्य डिस्प्ले पैनल के लगभग 4 से 5 प्रतिशत हिस्से के अनुरूप रखने का निर्देश दिया गया है।

इसका उद्देश्य उपभोक्ता की नजर सीधे उस पोषक तत्व पर पहुंचाना है, जिसकी अधिकता स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय हो सकती है। यह कनाडा जैसे देशों में अपनाई गई चेतावनी आधारित लेबलिंग व्यवस्था से प्रेरित है।

डिजिटल समय में पुस्तकों की दुनिया

डॉ. मोनिका भाम्भू कलाना

अमेरिका के प्रसिद्ध निबंधकार और दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, 'अगर हमारा किसी असाधारण बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति से सामना होता है, तब हमें पूछना चाहिए कि उसने कौन-सी पुस्तकें पढ़ी है?' दूसरों की पढ़ी पुस्तकों के बारे में जानना मुश्किल हैं, किन्तु यह सवाल अवश्य खड़ा होता है कि डिजिटल क्रान्ति और ऑनलाइन शिक्षा के इस जमाने में किताबें कहाँ हैं ? स्क्रीन से अलग मुद्रित किताब, जिसे हाथ में लेकर पढ़ा जा सके, वे कहाँ हैं, कितनी हैं और उनका भविष्य क्या है ? अब तक मनुष्य को अपने अतीत और भविष्य से जोड़ने वाली किताबों का भविष्य क्या सचमुच संकटमय है या तकनीकी संजाल में रूप बदलकर किताबें अब भी गतिमान हैं ? किताबें केवल साहित्य की ही नहीं होती किन्तु बहुतायत उन्हीं की होती है। इसलिए जब साहित्य के संकट की बात होती है तो उसका संकट पुस्तकों से भी जुड़ा होता है। गूगल बुक्स और किंडल जैसे एप्प की लगातार बढ़ती लोकप्रियता ने भौतिक पुस्तक के अस्तित्व पर अवश्य प्रश्नचिह्न लगाया है, किन्तु पुस्तकें तो पढ़ी जा रही हैं, उनके पाठक बढ़े हैं। पुस्तकों के पीडीएफ संस्करण की लोकप्रियता और खरीददारी बताती है कि तकनीक ने पुस्तकों के लिए संकट उपस्थित करने की बजाय उन्हें सस्ता और सुलभ बनाया है। पीडीएफ संस्करण ने पुस्तकों की पुस्तकालय तक बंद दुनिया को आमजन के लिए खोल दिया है। डिलीवरी ऐप्स के आने के बाद किताबों की दुनिया वही नहीं रही, जो पहले थी। किताबें उन सबके लिए सुलभ हुई जो उन्हें खरीद सकते थे। किन्तु किंडल जैसे ऐप के आने के बाद पुस्तकें नाममात्र की क़ीमत पर मिलने लगीं, जिसे दो-तीन लोग मिलकर भी खरीदकर पढ़ सकते हैं। अब पुस्तकों के लिए लाइब्रेरी कार्ड्स और दूर-दराज जाने की जरूरत नहीं रही। पुस्तकों की सॉफ्ट या डिजिटल कॉपी ने पुस्तकों की दुनिया में, सच्चे अर्थों में जनतन्त्र लाने का कार्य किया। ग्रामीण इलाकों में जहाँ अब तक पुस्तकालय न पहुँच सकें, पुस्तकें डिजिटल क्रान्ति पर सवार होकर पहुँची। दृष्टि बाधित लोगों के लिए ऑडियो बुक ने एक नई दुनिया खोल दी, वहीं मूक-बधिर लोगों के लिए वीडियो बुक ने यह दरवाजा खोला।

भारत में आज भी दुनिया में सर्वाधिक पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। यह सही है कि यहाँ साहित्यिक नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी पुस्तकें सर्वाधिक पढ़ी जाती है जिनका मूल्य परीक्षा उत्तीर्ण करने से अधिक नहीं होता। किन्तु किताबें छपती भी वही सबसे ज्यादा है, बिकती भी हैं और पढ़ी भी वही जाती हैं। 2022 के वैश्विक कल्चर इंडेक्स के अनुसार भारतीय लोग सप्ताह में औसतन दस घण्टे से अधिक पढ़ने में बिताते हैं। यह दुनिया में सर्वाधिक है। हर विषय की लिखित पुस्तकें उस विषय का साहित्य कहलाती है, किन्तु पुस्तकों का नाम आते ही रचनात्मक साहित्य की पुस्तकें ही यकायक ध्यान में आती है, इसीलिए जब भी साहित्य के अस्तित्व के संकट की बात की जाती है उसे किताबों के संकट से जोड़ा जाता रहा है। वैश्वीकरण के इस समय में पिछले तीस सालों से लगातार मानव जीवन में साहित्य की जरूरत और उसके स्थान को लेकर सवाल उठाया जाता रहा है, आपाधापी के इस युग में जब मनोरंजन के असीमित साधन हो साहित्य की अहमियत क्या हैं और किताबें क्यों पढ़ी जानी चाहिए, यह पूछना एक जरूरी सवाल है। किन्तु मनोरंजन के साधनों के बीच जब इतनी प्रतिस्पर्धा है तभी तो पुस्तक की असली परीक्षा होगी। कहते हैं साहित्य मनुष्य के आत्म का विस्तार करके उसे मनुष्य मात्र के प्रति सहानुभूतिमय और संवेदनशील बनाता है। यदि ऐसा है तो साहित्य की जरूरत बढ़ी ही है। सूचनाओं और जानकारियों को प्राप्त करने के साधन और गति जैसे-जैसे बढ़ी है मनुष्य में सहानुभूति और संवेदना कम होती गई है, मनोरंजन के तमाम साधन समय काटने के माध्यम से ज्यादा क्या हैं क्या इससे ज्यादा उनकी कोई भूमिका है ? इतनी सूचनाओं के होते हुए भी मनुष्य दूसरे तक पहुँचने में, स्वयं को संप्रेषित करने में सक्षम नहीं रहा है, अतः अकेला पड़ता गया है। लिखे हुए शब्द की क्षमता तक मनोरंजन के ये साधन नहीं पहुँच सकें। जब तक दूसरे को समझने-जानने और सत्य तक पहुँचने की ललक रहेगी पुस्तकें हमेशा रहेगी और साहित्य भी। पुस्तकों का रूप बदल रहा है लेकिन रूप का बदलाव समय की माँग है। छापे के आविष्कार के बाद जब साहित्य मौखिक से लिखित रूप में आया था, तो उसने ज्ञान पर कुछ लोगों और वर्गों के वर्चस्व को तोड़कर उसे पुस्तक के रूप में खरीददारों तक पहुँचा दिया। इससे साहित्य और पुस्तकें बढ़ी ही, उन्हें विस्तृत होने को नया आसमान मिल गया था। समाज में जब भी कोई बदलाव आता है तो साहित्य में भी बदलाव अवश्यम्भावी है। हर परिवर्तन वस्तु से अधिक रूप और शिल्प का परिवर्तन होता है और हर परिवर्तन साहित्य और इस दुनिया के बीच की दरार को भरने का काम करता है। कार्ल सागन कहते हैं पढ़ना समय की यात्रा करना है। समय जो सदैव है और यात्राएं भी, इसलिए पुस्तकों की यात्रा मनुष्य के लिए सदैव जरूरी है। पुस्तकें मनुष्य की यात्रा में सदैव सहभागी रही है, अब तक पुस्तकों से ही मनुष्य ने अपने इतिहास को समझा है अपने पूर्वजों को जाना है और भविष्य का नक्शा खींचा है। मनुष्य जैसा है उसके बनने में उसके द्वारा पढ़ी गई और जी गई पुस्तकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए पुस्तकों का बने रहना तो तय है, वे भविष्य में किस रूप में होंगी यह सवाल लाजिमी है। तकनीक ने पुस्तकों के बाजार को फैलाया है और अधिक लोगों तक पुस्तकों को पहुँचाया है। किन्तु पुस्तक को कागजी रूप में पढ़ना और सॉफ्ट रूप में पढ़ना दो भिन्न अनुभव होते हैं, ऐसे में यह शोध का विषय हो सकता है कि दोनों में क्या भिन्नताएँ होती है ? स्क्रीन पर पुस्तक को पढ़ना, पढ़ने जैसा अनुभव नहीं हो सकता है, इसमें एक तरीके से कार्य को निपटाने वाले दबाव शामिल होते हैं। दूसरे, आज जब यह सवाल उठता है कि मनुष्य स्क्रीन से अलग अपने लिए वक्त कैसे निकालें, ऐसे में स्क्रीन पर उपलब्ध पुस्तक मनुष्य के लिए वैसे दोस्त नहीं हो सकती जैसे कागज पर छपी किताबें रही हैं।

साहित्य मनुष्य अपने लिए वक्त निकालकर पढ़ता है, अपने साथ होने के लिए... किन्तु स्क्रीन पर पढ़ना कैसा अपने साथ होना है ? पुस्तकें तो सदैव बनी रहेगी किन्तु उनके हार्ड संस्करण का बने रहना भी जरूरी है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि रूप में परिवर्तन कई बार वस्तु की मूल पहचान को ही लुप्त कर देता है। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें ही नहीं, साहित्य की पुस्तक का भी कागज पर लगातार छपते रहना और पढ़े जाना आवश्यक है।

भारतीय रेलवे की ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक विकास का रजत सम्मान

विनोद सिंह

आईआईटीएफ-2026 में रजत पुरस्कार से सम्मानित हुआ रेलवे मंडप भाप इंजन से वंदे भारत स्लीपर तक 173 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का नया अध्याय; 99.6 प्रतिशत ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण,स्वदेशी कवच सुरक्षा प्रणाली और आधुनिक रेल तकनीक बनी दर्शको का बना आकर्षण केंद्र

भारतीय रेलवे की गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत,आधुनिक तकनीकी क्षमता और विकास की निरंतर यात्रा को 45वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ-2026) में राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारतीय अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार मेला 2026 में रेल मंत्रालय के मंडप को उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 'विकास और विरासत' की व्यापक अवधारणा पर आधारित इस आयोजन में भारतीय रेलवे की प्रदर्शनी ने आगंतुकों के साथ निर्णायक मंडल का भी विशेष ध्यान आकर्षित किया।यह सम्मान केवल एक आकर्षक प्रदर्शनी की उपलब्धि नहीं, बल्कि उस भारतीय रेल व्यवस्था की विकास यात्रा की गाथा का प्रतीक है,जिसने देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने में डेढ़ शताब्दी से अधिक समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय रेलवे का इतिहास केवल रेलगाड़ियों और पटरियों का इतिहास नहीं है, बल्कि यह आधुनिक भारत के निर्माण, औद्योगिक विकास, व्यापारिक विस्तार और राष्ट्रीय एकीकरण की एक जीवंत गाथा है। सर्व विदित रहे कि भारत में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली यात्री रेलगाड़ी ने लगभग 34 किलोमीटर की यात्रा शुरू की थी। उस ऐतिहासिक रेलगाड़ी में 14 डिब्बे और लगभग 400 यात्री सवार थे। भाप इंजन से शुरू हुई यह यात्रा धीरे-धीरे देश के दूरदराज के शहरों, कस्बों और गांवों तक पहुंची। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947 में विभिन्न रियासतों और निजी व्यवस्थाओं से जुड़ी 42 रेल प्रणालियों को एकीकृत कर भारतीय रेलवे के व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। आज यही रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। समय के साथ भारतीय रेलवे ने तकनीकी बदलावों को अपनाते हुए विकास की लंबी मंजिल तय की है।

वर्ष 1925 में मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला हार्बर के बीच पहली विद्युत रेल सेवा शुरू होना भारतीय रेल इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव था। भाप इंजनों के दौर से डीजल और फिर विद्युत इंजनों तक पहुंचने वाली इस यात्रा ने रेल परिचालन की गति, क्षमता और दक्षता को नई दिशा दी।

मंगल की ओर बढ़ते मानव कदम

योगेश कुमार गोयल

वैसे तो रात होते ही आसमान में बहुत सारे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं लेकिन इंसानों के लिए पृथ्वी के बगल में सदा से ही आकर्षण का केन्द्र रहा एक खूबसूरत लाल ग्रह मौजूद है, जिसे 'रेड प्लेनेट' अथवा 'मंगल' के नाम से जाना जाता है। मंगल ऐसा ग्रह है, जो रात के समय लाल रंग का दिखाई देता है। इसी लाल ग्रह के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रतिवर्ष 28 नवम्बर को 'लाल ग्रह दिवस' (रेड प्लेनेट डे) मनाया जाता है। यह दिवस 28 नवम्बर 1964 को नासा (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा अंतरिक्ष यान 'मेरिनर-4' के प्रक्षेपण की याद में मनाया जाता है, जो कई असफल मिशनों के बाद मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। करीब आठ महीने की यात्रा करने के बाद यह अंतरिक्ष यान 14 जुलाई 1965 को लाल ग्रह पर पहुंचा था। 28 नवम्बर 1964 को नासा ने जब पहली बार 'मेरिनर-4 रोबोटिक इंटरप्लेनेटरी प्रो' लांच किया था, तब अनौपचारिक छुट्टी की घोषणा की गई थी और सभी ने नासा की इस सफलता को उत्साहपूर्वक मनाया था। मेरिनर-4 को फ्लाई-बाय के दौरान डेटा एकत्र करने, ग्रहों की खोज और मंगल ग्रह के वैज्ञानिक अवलोकन को सक्षम करने तथा उस डेटा को पृथ्वी पर लोगों को वापस रिले करने के लिए बनाया गया था। अपने 228 दिनों के सफर को सफलतापूर्वक तय करने के बाद मेरिनर-4 पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना था, जिसे नासा द्वारा मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया था। उसी स्पेसक्राफ्ट ने मंगल ग्रह की तस्वीरें पहली बार दुनिया के सामने प्रस्तुत की थी।

अब तक 14 मंगल मिशन सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं, जहां मानव निर्मित वस्तुएं इस ग्रह पर उतरी। भारत भी इसरो के जरिये मंगल ऑर्बिट तक पहुंचने के अपने 'मंगल मिशन' में सफल हो चुका है। मंगल को जानने के लिए अब तक दुनियाभर में शुरू किए गए दो तिहाई अभियान असफल रहे हैं लेकिन भारत 24 सितम्बर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही विश्व में अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला देश तथा सोवियत रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगल पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बना था। सूर्य से चौथा ग्रह 'लाल ग्रह' यानी मंगल है और मंगल तथा पृथ्वी का गहरा संबध माना जाता रहा है। मंगल ग्रह पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है और अपने साथी स्थलीय ग्रहों की ही तरह इसमें भी एक केन्द्रीय कोर, एक चट्टानी आवरण और एक ठोस परत है। धूल भरी, ठंडी, रेगिस्तानी दुनिया में इसका वातावरण बहुत पतला है। मौसमों, ध्रुवीय बर्फ की चोटियों, घाटियों, विलुप्त ज्वालामुखी और इस बात के प्रमाण होने के साथ-साथ कि यह एक समय और भी अधिक सक्रिय था, मंगल एक गतिशील ग्रह है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी के कारण, मंगल ग्रह पर ऐसे मौसम का अनुभव होता है, जो अत्यधिक तापमान से बना होता है और तापमान -191 डिग्री फारेनहाइट से 81 डिग्री तक जा सकता है। लाल ग्रह के बारे में जानने के लिए कई एस्ट्रोनॉमी क्लब की भी शुरुआत की गई है, जो मंगल ग्रह से जुड़ी जानकारियों को एक-दूसरे से बांटने का काम करते हैं।

मंगल ग्रह के चारों ओर कोई वलय नहीं हैं। कई अध्ययनों से पता चल चुका है कि मंगल ग्रह पृथ्वी की स्थलाकृति से काफी मिलता-जुलता है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह अलग-अलग मौसम हैं लेकिन वे पृथ्वी पर मौसम की तुलना में अधिक समय तक रहते हैं। चूंकि मंगल ग्रह के बहुत से गुण पृथ्वी की तरह ही हैं, इसीलिए पृथ्वी के पर्यावरण की तरह मंगल के पर्यावरण को समझकर यह माना जाता है कि बहुत साल पहले मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव हुआ होगा और यह भी माना जाता है कि भविष्य में भी मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। सूर्य से बहुत दूर होने के कारण मंगल की कक्षा पूरी होने की गति बहुत धीमी है और इसी कारण मंगल ग्रह पर एक वर्ष में करीब 687 दिन बीतेंगे, जो पृथ्वी पर एक वर्ष से लगभग दोगुना समय है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में मंगल ग्रह को 1.88 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी का करीब एक-तिहाई है और गुरुत्वाकर्षण के विभिन्न खिंचाव के परिणामस्वरूप ही यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 100 पाउंड है तो अंतरिक्ष में उसका वजन केवल 38 पाउंड ही होगा।

यह जानना भी बहुत दिलचस्प है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? दरअसल यह आकाश में एक लाल सितारे के रूप में दिखाई देता है और इसकी सतह भी महीन रेत और आयरन ऑक्साइड से भरी धूल से ढ़की हुई होती है। मंगल ग्रह की सतह पर पाए जाने वाले तत्वों के कारण ही यह ग्रह लाल रंग का है। नासा के मुताबिक मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा में मौजूदगी है और वैज्ञानिकों के अनुसार जिस प्रकार ऑक्सीजन तथा नमी के सम्पर्क में आने पर पृथ्वी पर लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाती है, ठीक उसी प्रकार मंगल की मिट्टी में मौजूद लौह खनिज में जंग लग गया है और उसी कारण यह लाल नजर आती है। मंगल की सतह पर काफी मात्रा में लोहा है और जब यह ऑक्सीजन के अणुओं के साथ क्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे आम भाषा में जंग लगना भी कहते हैं। पृथ्वी अपने वायुमंडल के कारण नीले रंग की दिखाई देती है लेकिन मंगल का जंग जैसा लाल रंग इसकी मिट्टी में ऑक्सीकृत लोहे के कारण आता है। नासा के मुताबिक मंगल ग्रह पर बहुत सारी चट्टानें लोहे से भरी हुई हैं और जब वे बाहरी वातावरण के सम्पर्क में आती हैं तो ऑक्सीकरण करती हैं और लाल हो जाती हैं। जब उन चट्टानों से जंग लगी धूल वायुमंडल में फैलती है तो इससे मंगल ग्रह का आकाश लाल या गुलाबी दिखने लगता है। आयरन ऑक्साइड अथवा आयरन रस्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण ही मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है और इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है।



डाइट में शामिल करें खजूर

मिलते हैं स्वास्थ्य लाभ, डायबिटीज के मरीज भी खा सकते हैं

सर्दियों में सेहत को लेकर थोड़ी सी भी लापरवाही आपको बीमार कर सकती है। इस मौसम में खुद को स्वस्थ और फिट रखने के लिए अपनी डाइट में खजूर को शामिल करें। आहार विशेषज्ञों के अनुसार खजूर स्वास्थ्यप्रद सूखे फलों में से एक माना जाता है। अच्छे पोषक तत्वों से भरपूर और प्राकृतिक शर्करा से भरपूर, खजूर आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। इस ड्राई फ्रूट को सर्दियों का ड्राई फ्रूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। इसे खाने से रक्त संचार बढ़ता है और दिल और दिमाग को भी ताकत मिलती है। सर्दियों में शरीर को ज्यादा ऊर्जा और पोषण की जरूरत होती है। खजूर का नियमित सेवन आपको अंदर से मजबूत बनाता है और ठंड से बचाने में मदद करता है। इसकी मिठास और गर्म तासीर इसे सर्दियों के लिए परफेक्ट बनाती है।

खजूर, डेट पाल्म यानी पेड़ पर उगने वाला फल जिसे छुआरा भी कहते हैं। U.S. Department of Agriculture के मुताबिक खजूर में 67 कैलोरी और लगभग 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसी सूखे हुए खजूर में दो ग्राम फाइबर या फिर दिन भर में होने वाली फाइबर की खपत का आठ प्रतिशत होती है। इसके अलावा NCBI में छपे एक शोध के मुताबिक 100 ग्राम खजूर से 50–100% तक सुझाए गए डायटरी फाइबर मात्रा की पूर्ति होती है। इसके साथ ही डायटरी फाइबर कार्बोहाइड्रेट को शरीर में धीमी गति से सोखने में मदद करता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ने का खतरा कम हो जाता है।

तो आइए जानते हैं इस मौसम में इसे खाने से सेहत को क्या–क्या फायदे होते हैं और एक दिन में इसे कितना खाना चाहिए।

इन समस्याओं में फायदेमंद है खजूर

इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक

सर्दी–जुकाम और फ्लू ऐसी बीमारियाँ हैं जो सर्दियों में आम होती हैं। खजूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे आप ठंड में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं।

पाचन तंत्र स्वस्थ

खजूर खाने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है क्योंकि इसमें घुलनशील फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और इसमें अमीनो एसिड भी पाया जाता है।

कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है

खजूर में पोटैशियम की मात्रा अधिक और सोडियम की मात्रा कम होने के कारण यह शरीर के तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होता है। खजूर शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम रखकर आपके दिल के स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है।

ऊर्जा से भरपूर

खजूर में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसमें ग्लूकोज और सुक्रोज जैसी प्राकृतिक शर्कराएं भरपूर मात्रा में होती हैं। अगर आप खजूर को दूध के साथ लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठंड के दिनों में खजूर खाने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है। यही वजह है कि यह ठंडे इलाकों के लोगों का पसंदीदा फल है।

दिल और हड्डियों के लिए फायदेमंद

खजूर में पोटेशियम और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। साथ ही, यह दिल के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। सर्दियों में खजूर खाने से हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है।

गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद

खजूर गर्भवती महिलाओं को होने वाली कई तरह की समस्याओं से राहत दिलाता है। यह रक्तस्राव को कम करता है।

वजन बढ़ाए

अगर आप वजन घटने से परेशान हैं तो खजूर खाएं, क्योंकि इसमें मौजूद तत्व वजन बढ़ाने में सहायक होते हैं। शराब पीने से शरीर को होने वाले नुकसान से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।

कब और कैसे करें इसका सेवन?

रात को खजूर को पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। खाली पेट इसका सेवन करने से आप दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप दिन में 3 से 4 खजूर खा सकते हैं।

दूध के साथ: रात में सोने से पहले गर्म दूध में खजूर डालकर सेवन करने से शरीर को तुरंत गर्मी मिलती है।

ड्राई फ्रूट्स के साथ खजूर को बादाम, अखरोट और काजू के साथ खाया जा सकता है।

डेजर्ट में उपयोग: खजूर का इस्तेमाल के क और लड्डू में कर इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है।

डायबिटीज के मरीज भी खा सकते हैं खजूर

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि डायबिटीज के मरीज 1–3 खजूर खा सकते हैं। यदि उनका शुगर लेवल नियंत्रण में है और वे नियमित शारीरिक गतिविधि में हैं, फिर भी उन्हें डॉक्टर से परामर्श करने की आवश्यकता है। चूंकि खजूर सूख जाते हैं, उनकी कैलोरी सामग्री अन्य ताजे फलों की तुलना में अधिक हो जाती है। इसके अलावा, इस तथ्य को देखते हुए कि वे प्राकृतिक चीनी में उच्च हैं, उनकी खपत तत्काल ऊर्जा के कम होने की ओर ले जाती है।



खानपान ही नहीं कफ से भी मोटापा का संबंध, जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

आज के समय में बढ़ता वजन या मोटापा एक बड़ी समस्या बन चुकी है। अक्सर इसका दोष खान–पान पर मढ़ा जाता है। मगर कम ही लोग जानते हैं कि यह शरीर में बढ़ते 'कफ दोष' का भी नतीजा हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार, जब कफ और मेद (चर्बी) बढ़ जाता है, तो शरीर भारी होने लगता है, भूख कम लगती है, लेकिन वजन तेजी से बढ़ता है। इसे आयुर्वेद में 'स्थौल्य' कहते हैं। आयुर्वेद के विशेषज्ञ बताते हैं कि कफ का गुण ठंडक, भारीपन और स्थिरता हैं। यही गुण जब बढ़ जाते हैं, तो पाचन धीमा हो जाता है, मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ता है और चर्बी जमा होने लगती है। खासकर पेट, कूल्हे और जांघों में चर्बी बढ़ना कफ–प्रधान मोटापे का लक्षण है। कफ बढ़ने के मुख्य कारण पर नजर डालें तो ठंडी–भारी चीजें जैसे दही, आइसक्रीम, ज्यादा दूध का सेवन, देर तक सोना, कम चलना–फिरना, तला–भुना, मीठा और फास्ट फूड ज्यादा खाना, रात को देर से और भारी खाना, दिन में झपकी लेना और आलस्य वजह हैं।

आयुर्वेद में कफ–प्रधान मोटापे के लक्षण को भी बताया गया है। इसमें सुबह शरीर भारी लगना, कम भूख लेकिन मीठा खाने की तलब, चेहरा फूला–फूला सा रहना, पसीना कम आना, जल्दी थकना, सुस्ती और नींद ज्यादा आना और पाचन धीमा और कभी–कभी कब्ज की समस्या भी शामिल है।

आयुर्वेद कहता है कि कफ को संतुलित करने पर वजन अपने आप कम हो जाता है। इसके लिए कुछ आसान उपाय हैं, जैसे दिन की शुरुआत गुनगुने पानी या नींबू–शहद के पानी से करें। मूंग दाल, खिचड़ी, जौ, दलिया जैसे हल्के भोजन लें। करेला, मेथी, परवल, लहसुन–अदरक, हल्दी ज्यादा इस्तेमाल करें। मौसमी सब्जियां और फल लाभदायी हैं। मीठा, तला हुआ, दही, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक का सेवन न के बराबर करें। रात का खाना हल्का और जल्दी खाएं। सुबह जल्दी उठें।

सूर्य नमस्कार, कपालभाति, अग्निसार जैसे प्राणायाम करें और दिन में सोने से बचें और नियमित समय पर खाना खाएं। कफ दोष को संतुलित करने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वजन प्राकृतिक रूप से कम होने लगता है। कोई भी उपाय शुरू करने से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह जरूर से लेनी चाहिए। रात में मेथी दाना भिगोकर सुबह खाने से लाभ मिलता है। खाली पेट त्रिफला चूर्ण और दिन में छाछ में सेंधा नमक डालकर पीना भी लाभ देता है।

गाजर के सेवन से त्वचा, आंखों और बालों को मिलता है चमत्कारिक लाभ



वैसे तो सभी फल और सब्जियां सेहत के लिए फायदेमंद हैं। मगर सर्दियों के मौसम में खाई जाने वाली सबकी पसंदीदा गाजर सेहत के लिए बेहद ही लाभकारी है। गाजर के फायदे जानने के लिए आईएएनएस ने न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. स्वाति सिंह से बात की। न्यूट्रिशनिस्ट का काम डाइट और पौष्टिक आहार के सेवन से जुड़ी सामान्य जानकारी देना होता है। डॉ. स्वाति सिंह ने गाजर के फायदों पर बात करते हुए कहा, ''गाजर को बहुत सारे तरीके से खाया जा सकता है। आप गाजर को पकाकर या सलाद के तौर पर भी खा सकते हैं। इसका सूप बनाकर भी लिया जा सकता है। जो लोग इसे सब्जी के तौर पर नहीं ले सकते, वह इसका हलवा भी खा सकते हैं। गाजर को सर्दियों में अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चहिए, क्योंकि यह सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है।'' आगे न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. स्वाति सिंह ने बताया, ''गाजर में प्रचूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। कैलोरी की मात्रा इसमें बेहद कम होती है। जो लोग अपने वजन पर काम कर रहे हैं, उनके लिए गाजर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें 'विटामिन ए' भी मौजूद होता है। जो भूख को कम करने का काम करता है।''

न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा, ''गाजर में मौजूद फाइबर और पोटेशियम के कारण यह दिल के लिए भी लाभकारी होता है। यह ब्लड प्रेशर को भी सही रखने में मदद करता है। इसके अलावा, गाजर एंटी–एजिंग के प्रभाव को भी कम करने का काम करती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं।''

आगे उन्होंने कहा, ''गाजर के नियमित सेवन से आपके शरीर को कई तरह का लाभ मिलता है। यह आपकी त्वचा, आंखें और बालों के लिए बेहद फायदेमंद है। यह इम्यून सिस्टम पर भी बेहतर तरीके से काम करता है।''

उन्होंने आगे बताया, ''गाजर में विटामिन सी भी प्रचूर मात्रा में पाया जाता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। गाजर सर्दियों के लिए एक खास विकल्प है।'' गाजर में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। गाजर में मौजूद बीटा–कारोटीन आंखों के लिए फायदेमंद है। गाजर आपकी आंखों को इसकी वजह से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है।



साड़ी पहनने को लेकर इन फैशन टिप्स को न करें नजरअंदाज वरना बिगड़ सकता है पूरा लुक

साड़ी—एक ऐसा परिधान जो भारतीयता की आत्मा है, लेकिन गलत समय पर गलत साड़ी का चुनाव आपके पूरे लुक को बिगाड़ सकता है। चाहे पारंपरिक समारोह हो या ऑफिस का कोई फॉर्मल इवेंट, साड़ी हर मौके के लिए एक परिपूर्ण विकल्प बन सकती है, बशर्ते आप इसे पहनने के सही तरीके और मौके के अनुरूप स्टाइलिंग को समझें। आज के दौर में जहाँ फैशन एक स्टेटमेंट बन चुका है, वहाँ सिर्फ साड़ी पहन लेना ही काफी नहीं, बल्कि उसे सही रंग, कपड़े और डिजाइन के साथ पहनना ज़रूरी है, ताकि आपका लुक स्टाइलिश भी लगे और मौके के अनुरूप भी। अगर आप नहीं चाहतीं कि आपकी साड़ी स्टाइल बन जाए सोशल मीडिया का मज़ाक, तो पढ़िए ये खास टिप्स—ताकि हर नजर बस आप पर ही ठहर जाए।

अवसर के अनुसार चुनें साड़ी का फैब्रिक और डिज़ाइन

शादी, त्योहार या पारिवारिक समारोहों के लिए साड़ियों का चयन करते समय हैवी एंब्रॉयडरी, ज़री वर्क, बनारसी या सिल्क फैब्रिक वाली साड़ियाँ बेस्ट रहती हैं। इस तरह की साड़ियाँ न सिर्फ पारंपरिक लुक देती हैं बल्कि आपको भीड़ में अलग पहचान भी देती हैं। वहीं हल्की प्रिंटेड साड़ियाँ या सिंपल फैब्रिक इस मौके पर फीकी लग सकती हैं।

फॉर्मल मौकों पर हो स्मार्ट और सिंपल

ऑफिस पार्टी, मीटिंग या किसी प्रोफेशनल सेटिंग में यदि साड़ी पहननी हो, तो कॉटन, लिनेन, हैंडलूम या मलमल जैसी साड़ियों को चुनें। ये न केवल आपको एक एलिगेंट लुक देती हैं, बल्कि गर्मी के मौसम में आरामदायक भी होती हैं। ऐसे मौकों पर हल्के लेकिन ब्राइट रंग जैसे नीला, पिंक या पीच बेहतर प्रभाव डालते हैं।

सेमी–फॉर्मल फंक्शन में अपनाएं बैलेंस्ड स्टाइल

कभी–कभी ऐसे अवसर आते हैं जो न तो पूरी तरह पारंपरिक होते हैं, न ही पूरी तरह फॉर्मल। जैसे कि किसी दोस्त की इंगेजमेंट या छोटा पारिवारिक गेट–टुगेदर। ऐसे मौकों के लिए हल्की सिल्क साड़ियाँ जिसमें मिनिमल ज़री वर्क हो, पतला बॉर्डर हो और कलर टोन लाइट हो — ये सभी फैक्टर आपकी लुक को एलिगेंट बनाएंगे। चिकनकारी, थ्रेडवर्क या लेस डिटेल वाली साड़ियाँ भी ऐसे मौकों के लिए एकदम सही रहती हैं।

सैटिन साड़ी कब पहनें?

अगर आप ग्लॉसी लुक चाहती हैं तो सैटिन साड़ियाँ मॉकटेल पार्टी, संगीत या हल्के शादी समारोहों के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। सैटिन की चिकनाहट और फॉल आपकी बॉडी को खूबसूरत शेप देती है। इसे सिंपल ज्वेलरी और स्लीक हेयरस्टाइल के साथ स्टाइल करें तो यह लुक और भी रॉयल लगेगा।

साड़ी को लेकर एक्सपेरिमेंट करना अच्छा है, लेकिन मौके और माहौल के अनुसार स्टाइलिंग करना और भी जरूरी है। गलत साड़ी का चयन आपके पूरे लुक को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अगली बार जब भी साड़ी पहनें, इन फैशन टिप्स को ज़रूर ध्यान में रखें, ताकि हर नजर आप पर ही टिक जाए।

महिला आरक्षण और परिसीमन पर चंद्रबाबू नायडू-कुमारस्वामी ने किया समर्थन, लोकसभा की सीटें 50% बढ़ाने के प्रस्ताव का स्वागत



नई दिल्ली। महिला आरक्षण और लोकसभा परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार की पहल को अब दक्षिण भारत के प्रमुख नेताओं का समर्थन मिलने लगा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। चंद्रबाबू नायडू ने सभी राजनीतिक दलों से परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने की अपील की।

नायडू ने कहा कि लोकसभा की सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी से दक्षिण भारतीय राज्यों का संसद में मौजूदा प्रतिनिधित्व अनुपात प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि प्रस्ताव के तहत आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटें 25 से बढ़कर 38, तमिलनाडु की 39 से 59, कर्नाटक की 28 से 42, तेलंगाना की 17 से 26 और केरल की 20 से 30 हो सकती हैं।

उनके मुताबिक, पांचों दक्षिण भारतीय राज्यों की कुल लोकसभा सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी, लेकिन संसद में उनकी हिस्सेदारी 23.76 प्रतिशत पर बरकरार रहेगी।

नायडू ने कहा कि महिला आरक्षण लंबे समय से लंबित मुद्दा है और अब सभी दलों को महिलाओं को संसद में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने विपक्षी दलों से विधेयक पर अपना रुख स्पष्ट करने की भी अपील की। वहीं, एच.डी. कुमारस्वामी ने भी महिला आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 नवंबर को परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत लोकसभा की वर्तमान 543 सीटें बढ़ाकर लगभग 815 करने और राज्यों की मौजूदा आनुपातिक हिस्सेदारी 2051 तक बनाए रखने का प्रस्ताव है। संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें सरकार इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकती है।

सहकारिता से समृद्धि का मंत्र अपनाएं किसान, सामूहिक प्रयासों से मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

तीन सहकारी समितियों में आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम

किसानों को सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं की दी गई जानकारी आधुनिक खेती

फसल विविधीकरण और पशुपालन अपनाकर आय बढ़ाने के लिए किया प्रेरित



के.के.पी संवाददाता सितारगंज।(दीपक भारद्वाज)

किसानों को सहकारिता के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को क्षेत्र की तीन सहकारी समितियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को सहकारिता के महत्व, सरकारी योजनाओं, डिजिटल सेवाओं और कृषि से जुड़े नए अवसरों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने किसानों से संगठित होकर सहकारी समितियों का लाभ उठाने और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का आह्वान किया। बहुउद्देशीय दक्षिणी सितारगंज किसान सहकारी समिति लिमिटेड, क्रय-विक्रय सहकारी समिति तथा बिरिया दीर्घ सहकारी समिति में आयोजित स्केलिंग अप कार्यक्रम में सहकारी प्रबंध संस्थान देहरादून के व्याख्याता डॉ. अतुल भारद्वाज ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल लेन-देन या व्यवसाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसानों के आर्थिक और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

डॉ. भारद्वाज ने किसानों को सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही डिजिटल सेवाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने, आवश्यक दस्तावेज तैयार कराने और अन्य जनसुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता से ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए दूरस्थ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।

एक नजर

जागेश्वर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के लिए दीपक पाण्डेय ने पेश की दावेदारी



के.के.पी संवाददाता। अल्मोड़ा वर्ष 2027 में प्रस्तावित उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के लिए पूर्व प्रदेश मंत्री एवं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा उत्तराखंड दीपक पाण्डेय ने दावेदारी पेश की है।उन्होंने 53-जागेश्वर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी घोषित किए जाने के संबंध में अपना आवेदन पत्र जिला अध्यक्ष भाजपा अल्मोड़ा महेश नयाल को सौंपा।

इस अवसर पर दीपक पाण्डेय ने पार्टी संगठन के प्रति निष्ठा एवं लंबे समय से किए जा रहे संगठनात्मक कार्यों का उल्लेख करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में जागेश्वर क्षेत्र से अवसर प्रदान किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की।

भवन निर्माण नियमों एवं भू-उपयोग परिवर्तन में छूट के निर्णय पर दर्जा राज्यमंत्री भावना मेहरा ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संवेदनशीलता के साथ जनभावनाओं का सम्मान करते हुए जनहित में निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री हैं।



के.के.पी संवाददाता/भीमताल। भीमताल सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्राधिकरण के भवन निर्माण नियमों में शिथिलीकरण एवं भू-उपयोग परिवर्तन (लैंड यूज चेंज) में एक चौथाई तक छूट दिए जाने के निर्णय पर आवास सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष (दर्जा राज्यमंत्री) भावना मेहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है भावना मेहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं जो जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय लेते हुए आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं उन्होंने क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को गंभीरता से समझते हुए उन्हें राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है कहा कि वह लगातार प्राधिकरण क्षेत्र में भवन निर्माण नियमों एवं भू-उपयोग परिवर्तन से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाती रही हैं मुख्यमंत्री के प्रयासों से इन विषयों को कैबिनेट बैठक में लाया गया और जनहित में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया जिसके लिए आम जनमानस की तरफ से वे उनका आभार व्यक्त करती है कहा कि मुख्यमंत्री निरंतर जनभावनाओं के अनुरूप फैसले लेकर प्रदेशवासियों को राहत पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण एवं उनके आर्थिक हितों के प्रति भी प्रतिबद्ध है आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि का निर्णय उनके अथक परिश्रम समर्पण एवं सेवाभाव के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सम्मान को दर्शाता है भावना मेहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनहित विकास एवं जनसमस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है।

स्वास्थ्य निदेशक ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा



के.के.पी संवाददाता/अल्मोड़ा। चिकित्सा स्वास्थ्य निदेशक कुमाऊं मंडल डॉ. केके अग्रवाल ने शुक्रवार को जिला अस्पताल अल्मोड़ा का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। करीब एक घंटे चले निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर, आकस्मिक विभाग, ओपीडी, आईसीयू, ऑपरेशन थियेटर, ऑडियोमेट्री, प्रसूति संबंधी व्यवस्थाओं, बायोगैस एवं अन्य संयंत्रों तथा अग्निशमन यंत्रों की जांच की। निदेशक ने विभिन्न विभागों में उपलब्ध व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ मरीजों से बातचीत कर उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कुछ व्यवस्थाओं में कमियां भी सामने आईं, जिनका संज्ञान लेते हुए उन्होंने आवश्यक सुधार पर जोर दिया। संबंधित कमियों से उच्च अधिकारियों और अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अवगत कराकर सुधारात्मक कदम उठाने की बात कही गई। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एचसी गड़कोटी ने बताया कि निदेशक अस्पताल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट रहे।

लोन समाप्त कराने और ब्याज में छूट का झांसा देकर महिला से 1.49 लाख रुपये ठगे

फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बनकर किया फोन, रकम जमा कराने के बाद एनओसी देने से मुकरा आरोपी

दो अलग-अलग बैंक खातों से ट्रांसफर कराई रकम, पीड़िता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

के.के.पी संवाददाता सितारगंज (दीपक भारद्वाज)।

फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बनकर साइबर ठग ने एक महिला को लोन समाप्त कराने और ब्याज में 75 हजार रुपये की छूट दिलाने का झांसा देकर 1.49 लाख रुपये की ठगी कर ली। आरोपी ने महिला को विश्वास दिलाया कि उसके लोन का रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए कंपनी की ओर से उसे विशेष छूट दी जा रही है। ठग की बातों में आकर महिला ने अपने और पति के बैंक खातों से बताए गए खाते में रकम स्थानांतरित कर दी। इसके बाद जब महिला ने लोन समाप्त होने का प्रमाणपत्र (एनओसी) मांगा तो आरोपी टालमटोल करने लगा। काफी प्रयास के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर महिला को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास हुआ। पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है।

गांव गौरीखेड़ा निवासी इफरा मलिक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पति का आईडीबीआई बैंक में खाता है, जबकि उनका स्वयं का खाता यश बैंक की सितारगंज शाखा में है। दोनों बैंक खाते मोबाइल नंबरों से जुड़े हुए हैं। आरोप है कि बीते 23 नवंबर को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को एक निजी फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताया। उसने महिला से कहा कि उनके ऊपर करीब तीन लाख रुपये का ऋण चल रहा है। उनके ऋण खाते का रिकॉर्ड अच्छा होने के कारण कंपनी की ओर से उन्हें 75 हजार रुपये की ब्याज छूट दी जा रही है।

आरोपी ने महिला को बताया कि यदि वह तत्काल करीब डेढ़ लाख रुपये जमा कर देती हैं तो उनका पूरा ऋण समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही उन्हें ऋण समाप्त होने का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) भी जारी कर दिया जाएगा। आरोपी ने इस पूरी प्रक्रिया को आसान बताते हुए महिला को भरोसे में ले लिया। महिला को लगा कि वास्तव में कंपनी की ओर से उन्हें राहत दी जा रही है। इसी विश्वास में उन्होंने आरोपी के बताए बैंक खाते में कुल 1,49,756 रुपये भेज दिए। पीड़िता के अनुसार, उन्होंने 25 नवंबर को अपने एक बैंक खाते से 59,756 रुपये और दूसरे बैंक खाते से 90 हजार रुपये स्थानांतरित किए। दोनों खातों से रकम भेजने के बाद उन्होंने आरोपी से संपर्क कर ऋण समाप्त होने का प्रमाणपत्र मांगा, लेकिन आरोपी लगातार उन्हें टालता रहा। कभी प्रक्रिया पूरी होने की बात कही तो कभी बाद में प्रमाणपत्र देने का आश्वासन दिया। जब काफी समय तक एनओसी नहीं मिली और आरोपी ने स्पष्ट जवाब देना बंद कर दिया तो महिला को संदेह हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है।

इसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी जुटाई और सितारगंज कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर सौंपी। उन्होंने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ठगी गई रकम वापस दिलाने और उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

एसएसपी मणिकांत मिश्रा की पुन : तैनाती पर उद्योगपतियों व समाजसेवियों ने किया स्वागत-अभिनंदन



के.के.पी संवाददाता

रुद्रपुर, क्षेत्र के उद्योगपति व समाजसेवियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा की जिले में पुनः तैनाती होने पर उनके कार्यालय पहुंचकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस दौरान उद्योगपति मनोज गुप्ता, समाजसेवी मनीष तिवारी, भाजपा किसान मोर्चा आईटी सेल प्रभारी व वरिष्ठ समाजसेवी धनंजय सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का स्वागत करते हुए क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं एवं औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की। उद्योगपतियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पुनः जिले में तैनाती से उद्योगों और पुलिस प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया तथा कहा कि उनकी तैनाती से उद्योगों की सुरक्षा और उद्यमियों का विश्वास और अधिक मजबूत होगा व साथ ही क्षेत्रवासियों की सुरक्षा व्यवस्था भी अधिक मजबूत होगी।

बैगुलडाम क्षेत्र में 426 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण

434 परिवारों का कब्जा

वन विभाग ने अतिक्रमित भूमि खाली कराकर पौधरोपण कराने पर दिया जोर

वर्ष 1969 में सिंचाई विभाग को हस्तांतरित हुई थी जमीन

के.के.पी संवाददाता

सितारगंज। लौका-बैगुलडाम क्षेत्र में सरकारी और वन भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने भूमि की स्थिति स्पष्ट की है। बाराकोली वन क्षेत्र के वन क्षेत्राधिकारी महेंद्र सिंह रेकुनी ने बताया कि बैगुलडाम क्षेत्र में कुल 426.13 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण की चपेट में है। इस भूमि पर 434 परिवारों का कब्जा है। विभाग का कहना है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उसका उपयोग पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण के लिए किया जाना आवश्यक है। वन क्षेत्राधिकारी रेकुनी ने बताया कि वर्ष 1969 में कोर्ट खर्रा और बाराकोली वन क्षेत्र की कुल 1583.50 हेक्टेयर भूमि सिंचाई विभाग को हस्तांतरित की गई थी। इसमें से अतिक्रमण की चपेट में आई भूमि को खाली कराकर वन विभाग को वापस किया जाना प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक यह भूमि वन विभाग को वापस नहीं मिल सकी है। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना जरूरी है। भूमि खाली होने के बाद वहां बड़े पैमाने पर पौधरोपण कराया जाना चाहिए, ताकि क्षेत्र को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सके। इससे एक ओर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर भविष्य में भूमि पर दोबारा अतिक्रमण होने की आशंका भी कम होगी। रेकुनी ने बताया कि शासन की ओर से वर्ष 1975 में जारी आदेश में भी अतिक्रमित भूमि को खाली कराकर वहां वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि भूमि मुक्त होने के बाद केवल पौधरोपण कराना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसकी नियमित निगरानी, सुरक्षा और पौधों की देखभाल की व्यवस्था भी जरूरी है।

नवागत एसएसपी नैनीताल श्री अर्पण यदुवंशी IPS ने जनपद में आगमन के पश्चात् हनुमान मंदिर के दर्शन कर संभाला नैनीताल जनपद का कार्यभार



हल्द्वानी। अर्पण यदुवंशी IPS वर्ष 2017 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी ने काठगोदाम स्थित श्री हनुमान मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया तत्पश्चात् नैनीताल जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री यदुवंशी अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और परिणाममुखी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। अपने अब तक के सेवाकाल में उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है।

पुलिस कार्यालय हल्द्वानी पहुंचने पर सर्वप्रथम सलामी गार्द द्वारा सलामी दी गई, इसके उपरांत नैनीताल पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया।

सेवाकाल के प्रमुख कार्य:

पुलिस अधीक्षक, रेलवे (GRP): रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में कानून-व्यवस्था व यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। रेलवे संबंधी अपराधों की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभाई।

पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी: करीब 2.5 वर्षों तक जनपद में कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण का संचालन किया। गंगोत्री-यमुनोत्री यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया। इसी कार्यकाल में उन्होंने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान का घटना कमांडर के रूप में नेतृत्व किया। विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सेनानायक, राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF): लगभग 2 वर्षों तक SDRF का नेतृत्व किया।

- प्रयागराज महाकुंभ 2025: एक माह तक SDRF की तैनाती और संचालन का नेतृत्व किया।

- धराली आपदा, अगस्त 2025: 1386 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया और 17,000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया।

- उनके नेतृत्व में SDRF उत्तराखंड का पहला ऐसा आपदा बल बना जिसे ISO 9001:2015 का प्रमाणन प्राप्त हुआ।

- कार्यकाल में लगभग 1,80,000 लोगों को आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान: श्री यदुवंशी ने BRICS आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया और सिलक्यारा बचाव अभियान के अनुभवों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साझा किया। उन्होंने हृष्टतत, रुक्ष्ह और सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जैसे संस्थानों में आपदा प्रबंधन पर व्याख्यान भी दिए।

प्रमुख सम्मान:

उनके कार्यों के लिए उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रशंसा-पत्र, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक 2024, महाकुंभ सेवा पदक 2025, अमेरिकी दूतावास का प्रशंसा पदक और हृष्ठरू से प्रशस्ति, पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क सिल्वर सहित कई सम्मान प्राप्त हुए हैं।

नवनियुक्त एसएसपी श्री अर्पण यदुवंशी के अनुभव और नेतृत्व से नैनीताल पुलिस बल जनपद में कानून-व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ तथा जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

प्रमुख पशु रोगों से बचाव के लिए ग्रामीणों को किया जागरूक, 305 पशुओं का किया उपचार

57वीं वाहिनी एसएसबी ने बनमहोलिया में लगाया नि :शुल्क पशु चिकित्सा शिविर, 32 ग्रामीण हुए लाभान्वित

पशुओं के उपचार के साथ डेयरी उद्योग और ऋण योजनाओं की भी दी जानकारी



के.के.पी संवाददाता

सितारगंज।(दीपक भारद्वाज) भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों को पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य और पशुपालन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 57वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की ओर से वाइब्रेंट ग्राम बनमहोलिया में निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पशु चिकित्सकों ने कुल 305 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका उपचार किया और ग्रामीणों को आवश्यक दवाइयां निःशुल्क वितरित कीं। इस जनकल्याणकारी पहल से गांव के 32 ग्रामीणों को सीधा लाभ मिला।

शिविर का आयोजन 57वीं वाहिनी एसएसबी के कार्यवाहक कमांडेंट जसबीर सिंह के निर्देशानुसार किया गया। सीमांत मुख्यालय रानीखेत से पहुंचे कमांडेंट (पशु चिकित्सा) डॉ. ए.के. सिंह के नेतृत्व में पशु चिकित्सकों की टीम ने ग्रामीणों के पशुओं की जांच की। इस दौरान गाय, भैंस सहित अन्य पशुओं के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें होने वाली बीमारियों के लक्षणों और उपचार के संबंध में जानकारी दी गई। जरूरत के अनुसार पशुओं को दवाइयां भी उपलब्ध कराई गईं। शिविर के दौरान पशु चिकित्सकों ने ग्रामीणों को पशुओं में होने वाली विभिन्न संक्रामक और मौसमी बीमारियों के प्रति जागरूक किया। विशेष रूप से बाढ़ के बाद फैलने वाले रोगों से बचाव के उपाय बताए गए। इसके साथ ही खुरपका-मुंहपका, गलघोंटू, मिल्क फीवर और कीटोसिस जैसी बीमारियों के लक्षण, समय पर उपचार और रोकथाम की जानकारी दी गई। चिकित्सकों ने बताया कि पशुओं को बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए समय-समय पर टीकाकरण, स्वच्छता, संतुलित आहार और उचित देखभाल बेहद जरूरी है। पशुओं के रहने के स्थान को साफ-सुथरा रखने तथा बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल पशु चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह भी दी गई।

पशु चिकित्सा शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को केवल उपचार ही नहीं, बल्कि पशुपालन को रोजगार और आय का बेहतर साधन बनाने के संबंध में भी जानकारी दी गई। पशु चिकित्सकों ने ग्रामीणों को डेयरी उद्योग की संभावनाओं, वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करने तथा दूध उत्पादन बढ़ाने के उपायों से अवगत कराया। इसके अलावा ग्रामीणों को नाबार्ड के माध्यम से उपलब्ध ऋण सुविधाओं और योजनाओं की जानकारी देते हुए स्वरोजगार के लिए इनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य आरक्षी हरमुख सिंह सहित एसएसबी के जवान और क्षेत्र के गणमान्य ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने सीमावर्ती गांव में इस प्रकार का निःशुल्क शिविर आयोजित करने के लिए एसएसबी का आभार जताया और इसे पशुपालकों के लिए उपयोगी पहल बताया।

शिविर के समापन पर कमांडेंट (पशु चिकित्सा) डॉ. ए.के. सिंह ने आयोजन में सहयोग करने वाले सभी अधिकारियों, जवानों और ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को स्वास्थ्य, पशुपालन और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाओं के प्रति जागरूक करना ऐसे कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने भविष्य में भी इस प्रकार के जनकल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित करते रहने का आश्वासन दिया।

कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

के.के.पी संवाददाता

1. उत्तराखण्ड सफाई कर्मचारी आयोग के अन्तर्गत उपाध्यक्ष का 01 अतिरिक्त पद सृजित किए जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

2. केंद्र सरकार द्वारा संगठित, असंगठित एवं अन्य क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों और कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा का विस्तार देने के उद्देश्य से लागू सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 154 एवं 156 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली, 2026 प्रख्यापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। नियमावली के लागू होने से संगठित एवं असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जाएगा। असंगठित कर्मकारों एवं भवन संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण हेतु पृथक-पृथक बोर्डों के गठन का प्रावधान किया गया है। कर्मकार द्वारा नामांकित व्यक्ति या उत्तराधिकारी के नाबालिग होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा उसके वयस्क होने तक ग्रेच्युटी राशि भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा में निवेश किए जाने का प्रावधान है। कर्मकारों के नामांकन की रीति एवं प्रारूप निर्धारित किए गए हैं। कर्मकार की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के व्यय हेतु राशि सक्षम प्राधिकारी के पास जमा किए जाने का प्रावधान है। कर्मचारी बीमा न्यायालय की संरचना एवं नियंत्रण आदि के सम्बन्ध में प्रावधान किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा कोष का गठन कर असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

3. कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) की सीधी भर्ती के पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता में डी.फार्मा के अतिरिक्त बी.फार्मा को सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में।

इस हेतु कैबिनेट द्वारा उत्तराखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा योजना फार्मासिस्ट संवर्ग (एलोपैथिक) सेवा नियमावली, 2021 के नियम-8 (शैक्षिक अर्हता) में संशोधन करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा योजना फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2026 प्रख्यापित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

1. पेराई सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंकों से ऋण लिए जाने हेतु शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किए जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय



राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को पेराई सत्र में गन्ना किसानों को समय पर गन्ना मूल्य भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा शासकीय प्रत्याभूति प्रदान की जाती रही है। पेराई सत्र 2026-27 हेतु चीनी मिल बाजपुर, नादेही, किच्छा एवं डोईवाला के लिए कुल ?207.75 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

1. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत एक्स-रे टेक्नीशियन सेवा में भर्ती तथा नियुक्त कार्मिकों की सेवा शर्तों को विनियमित किए जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड एक्स-रे प्राविधिज्ञ सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

2. राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों हेतु अनिवार्य राजकीय सेवा सम्बन्धी बॉण्ड अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों से अनिवार्य राजकीय सेवा सम्बन्धी बॉण्ड निष्पादित कर पी.जी. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात संबंधित चिकित्सकों को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दुर्गम/पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित चिकित्सालयों में 02 वर्ष की अनिवार्य राजकीय सेवा हेतु नियुक्ति प्रदान की जाती रही है। सीनियर रेजीडेन्ट चिकित्सकों की कमी को देखते हुए पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों हेतु अनिवार्य राजकीय सेवा सम्बन्धी बॉण्ड अनुमन्य किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।

7.उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव नीति, 2026 के प्रख्यापन को मिली मंजूरी

वर्तमान में प्रचलित ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख-रखाव नीति, 2024 को अधिक्रमित कर उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव नीति, 2026 प्रख्यापित किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।

8.उत्तराखण्ड राज्य में विविध निर्माण कार्यों हेतु सूचीबद्ध कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) को सूचीबद्ध पैनल से हटाए जाने का कैबिनेट ने लिया निर्णय

एनएचआईडीसीएल को शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। आवास विभाग द्वारा उक्त संस्था को राज्य के पाँच जनपदों में ऑटोमेटेड/मैकेनाइज्ड/टनल पार्किंग से सम्बन्धित आवंटित निर्माण कार्यों में रुचि न दिखाए जाने तथा निर्गत धनराशि के सापेक्ष दीर्घ समयावधि में भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न किए जाने के दृष्टिगत समस्त पार्किंग/विविध निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था की सूची से हटाए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिमण्डल द्वारा निर्णय लिया गया।

9.उत्तराखण्ड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र का तत्काल प्रभाव से सत्रावसान किए जाने को मंत्रिमण्डल ने दी संस्तुति।

10.उत्तराखण्ड सेतु आयोग सूचना प्रौद्योगिकी सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंत्रिमण्डल ने दिया अनुमोदन।

नियोजन विभागान्तर्गत सेतु आयोग, उत्तराखण्ड के संगठनात्मक ढाँचे को स्वीकृति प्रदान की गई है। विभागीय कार्यों के सुचारू संचालन हेतु तकनीकी एवं अन्य कार्यों के सम्पादनार्थ सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्मिकों की सेवा शर्तों के विनियमन हेतु उत्तराखण्ड सेतु आयोग सूचना प्रौद्योगिकी सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंत्रिमण्डल ने दिया अनुमोदन।

11.उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा राजपत्रित सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंत्रिमण्डल का अनुमोदन।

उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा राजपत्रित सेवा नियमावली, 2019 के अन्तर्गत अधिमानी अर्हता सम्बन्धी बिन्दु-9 एवं नियमावली के अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता के दृष्टिगत अधिमानी अर्हता सम्बन्धी धारा-9 के भाग (1) में 'प्रादेशिक सेवा' के स्थान पर 'प्रादेशिक सेना' किया जाना प्रस्तावित है, जिससे भविष्य में सहायक निदेशक/लेखा परीक्षा अधिकारी (पे मैट्रिक्स लेवल-10) की सीधी भर्ती के अधियाचन में विसंगति उत्पन्न न हो।

12.आबकारी विभागान्तर्गत उप आबकारी आयुक्त के 05 एवं सहायक आबकारी आयुक्त के 06 नवीन पदों, अर्थात कुल 11 नवीन पदों के सृजन के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

आबकारी विभागान्तर्गत अधिक से अधिक राजस्व संग्रहण, अवैध मदिरा की पूर्ण रोकथाम एवं विभागीय कार्यावश्यकता के दृष्टिगत वर्तमान में सृजित 02 परिक्षेत्रों को 07 परिक्षेत्रों में पुनर्गठित करते हुए प्रत्येक परिक्षेत्र में 01-01 उप आबकारी आयुक्त का पद निर्धारित किया गया है। इस प्रकार उप आबकारी आयुक्त (वेतन लेवल-11) के 05 नवीन पद तथा राज्य में स्थापित डिस्टलरीज/ब्रूवरीज हेतु सहायक आबकारी आयुक्त (वेतन लेवल-10) के 06 नवीन पद, अर्थात कुल 11 नवीन पदों का सृजन किया गया है।

13.महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभागान्तर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मासिक मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव पर निर्णय हेतु मंत्रिमण्डल द्वारा मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

14. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा डॉ. दिनेश चन्द्र ध्यानी, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक (प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग) को समान सेवा लाभ प्रदान किए जाने से सम्बन्धित प्रकरण पर मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन दिया गया।

15. जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास शुल्क के रूप में लिए जाने वाले अंशदान एवं क्षतिपूर्ति शुल्क में परिवर्तन के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास शुल्क को भारत सरकार के अनुरूप 10 प्रतिशत (15 प्रतिशत के स्थान पर) करते हुए जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास शुल्क की 5 प्रतिशत दर को क्षतिपूर्ति शुल्क में सम्मिलित कर क्षतिपूर्ति शुल्क को 15 प्रतिशत (10 प्रतिशत के स्थान पर) किया गया है तथा पूर्व में रॉयल्टी की बढ़ी हुई दरें स्थगित रहेंगी।

16. उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली, 2025 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

राजस्व विभाग के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक (सुपरवाइजर कानूनगो) एवं रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों पर पदोन्नति पोषक संवर्ग (पटवारी/लेखपाल) से वरिष्ठता के आधार पर करने तथा पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के समान राजस्व निरीक्षक/रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों को एकीकृत करते हुए राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) पद पर मौलिक नियुक्ति की वरिष्ठता के अनुसार नायब तहसीलदार/सहायक भूलेख अधिकारी के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था हेतु कैबिनेट द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली बनाये जाने के संबंध में मंत्रिमण्डल की उप समिति बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

17. वन आरक्षी पद पर सीधी भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष किए जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली, 2016 (यथासंशोधित, 2018 एवं 2026) के अन्तर्गत वन आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रावधानों के अनुरूप दिनांक 31.12.2028 तक सीधी भर्ती हेतु वन आरक्षी पद की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष किए जाने के उद्देश्य से नियम-10 में आवश्यक संशोधन करते हुए उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 प्रख्यापित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

18. भवन उपयोग के आधार पर भू-खण्ड क्षेत्रफल की सीमा का वर्गीकरण करते हुए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 के मानकों से शिथिलीकरण प्रदान किए जाने हेतु स्तर निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों की परिस्थितियों के दृष्टिगत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम के मानकों से शिथिलीकरण प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में कार्य की प्रकृति के अनुरूप पृथक-पृथक सक्षम स्तर का निर्धारण कर प्रकरणों का सुगमतापूर्वक एवं समयबद्ध निस्तारण करने हेतु शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए भवन उपयोग के आधार पर भू-खण्ड क्षेत्रफल की सीमा का वर्गीकरण कर शिथिलीकरण का स्तर निर्धारित किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।

19. महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निर्धारित शुल्क में संशोधन के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

वर्तमान में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की दरें अव्यावहारिक होने तथा स्थानीय स्तर पर भूमि की सर्किल दर अधिक होने के कारण भू-स्वामी एवं विकासकर्ता वैधानिक स्वीकृति लेने से बच रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप अवैध, अनियंत्रित एवं अनियोजित निर्माण/प्लॉटिंग की स्थिति बढ़ रही है, जिससे महायोजना का मूल स्वरूप प्रभावित होने की सम्भावना है। नियोजित एवं वैधानिक विकास को गति प्रदान करने, ईओडीबी को बढ़ाने, निजी विकासकर्ताओं द्वारा अवस्थापना निर्माण को प्रोत्साहित करने, शासकीय बजट पर पड़ने वाले संभावित वित्तीय भार को रोकने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों को पुनर्जीवित करने, प्राधिकरण को वर्तमान वित्तीय संकट से उबारने तथा भूमि विवादों की संभावनाओं को न्यूनतम करने के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 01.08.2025 द्वारा निर्धारित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की व्यवस्था के स्थान पर शासनादेश दिनांक 06.10.2021 के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की दरें निर्धारित किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।

20. हरिद्वार शहर में पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (पीआरटी) (पॉड टैक्सी) 'हरिद्वार दर्शन' परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

हरिद्वार शहर में विश्वसनीय एवं सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के रूप में पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की स्थापना प्रस्तावित है। यह पृथक ग्रिड पर संचालित होने वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। प्रस्तावित मार्ग/रूट इस प्रकार हैं-

कॉरिडोर-1 में सीतापुर से भारत माता मंदिर तक का मार्ग प्रस्तावित है। इसकी लंबाई 15.58 किलोमीटर होगी और इस पर 15 स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं। कॉरिडोर-2 में सिटी हॉस्पिटल से दक्ष मंदिर तक का मार्ग प्रस्तावित है। इसकी लंबाई 3.10 किलोमीटर होगी और इस मार्ग पर 4 स्टेशन प्रस्तावित हैं।

वहीं कॉरिडोर-3 में गणेशपुरम से डीएवी स्कूल तक का मार्ग प्रस्तावित है। इसकी लंबाई 2.40 किलोमीटर होगी और इस पर 2 स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं। इस प्रकार तीनों प्रस्तावित कॉरिडोर की कुल लंबाई 21.08 किलोमीटर तथा कुल प्रस्तावित स्टेशनों की संख्या 21 होगी।

परियोजना के निर्माण हेतु कुल 6.9555 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें 6.1171 हेक्टेयर सरकारी भूमि तथा 0.8384 हेक्टेयर निजी भूमि है। निर्माण सामग्री, औजार, मशीनरी एवं अन्य कार्यों हेतु अतिरिक्त 2.00 हेक्टेयर अस्थायी भूमि की आवश्यकता 05 वर्षों के लिए होगी। उक्त अस्थायी भूमि प्रस्तावित पी.आर.टी. डिपो, सीतापुर के समीप चिन्हित की गई है।

21. बापूग्राम आरक्षित वन, ऋषिकेश की 594.90 एकड़ अधिसूचित वन भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन एवं भावी कार्यवाही हेतु वन भूमि को डीनॉटीफाई करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई है। इस प्रकरण में प्रस्ताव वन विभाग द्वारा दिया जायेगा।

22. उत्तराखण्ड महाधिवक्ता कार्यालय अधिष्ठान (कर्मचारियों की सेवा) नियमावली, 2013 में अग्रेत्तर संशोधन करते हुए उत्तराखण्ड महाधिवक्ता कार्यालय अधिष्ठान (कर्मचारियों की सेवा) (संशोधन) नियमावली, 2026 प्रख्यापित किए जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

23. आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में 1700 रूपये प्रतिमाह वृद्धि किये जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

बेतालघाट में ग्रामीण समुदाय को सौंपी गई विकास गतिविधियों की

40 गांवों के 120 किसानों ने लिया कार्यक्रम में भाग, सामुदायिक स्वामित्व एवं विकास गतिविधियों के स्थायित्व पर दिया गया जोर

के.के.पी संवाददाता

बेतालघाट, 27 नवंबर 2026। ग्रामीण समुदाय को विकास गतिविधियों के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में S.M. Sehgal Foundation एवं HDFC Bank Parivartan Project के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को बेतालघाट में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के 40 गांवों से 120 किसानों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।



कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परियोजना के अंतर्गत विकसित विभिन्न विकास गतिविधियों का स्वामित्व ग्रामीण समुदाय को सौंपना तथा उनके नियमित संचालन, रखरखाव और बेहतर प्रबंधन के लिए समुदाय को जिम्मेदार एवं सक्षम बनाना रहा। इस पहल के माध्यम से ग्रामीणों में सामुदायिक सहभागिता, आपसी सहयोग और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया।

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को परियोजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही, विभिन्न गतिविधियों के मॉडल प्रस्तुत कर उनकी कार्यप्रणाली, उपयोगिता और ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले लाभों के बारे में विस्तार से समझाया गया। प्रतिभागियों को बताया गया कि सामूहिक प्रयासों एवं नियमित देखरेख के माध्यम से इन गतिविधियों को लंबे समय तक प्रभावी और सुचारू रूप से संचालित रखा जा सकता है।

कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया। उद्यान विभाग से जे.एस. देवल एवं वर्षा थापा, ग्राम उद्यान से महेश पुरी, ग्राम विकास विभाग से ग्राम विकास अधिकारी देवेंद्र कुमार, NRLM Livelihood से महेश पुरी, बिजनेस प्रमोटर अनीता जलाल तथा स्वास्थ्य विभाग से तृप्ति एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) अंजली उपस्थित रहीं।

इसके अतिरिक्त S.M. Sehgal Foundation की ओर से एन.पी. सिंह, आकांक्षा, मेघ, सौरभ महंता सहित अन्य टीम सदस्यों तथा HDFC Bank के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की।

इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को अपने-अपने विभागों के माध्यम से संचालित सरकारी योजनाओं, सेवाओं और आजीविका संवर्धन के अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जुड़ने तथा उपलब्ध सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में S.M. Sehgal Foundation द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों एवं समुदाय के सशक्तीकरण के प्रयासों की सराहना करते हुए भविष्य में भी विभागीय समन्वय और सहयोग बनाए रखने का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि विकास कार्यों की वास्तविक सफलता केवल सुविधाओं के निर्माण तक सीमित नहीं होती, बल्कि उनके निरंतर संचालन, रखरखाव और स्थायित्व में निहित होती है। इसके लिए ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी, सामूहिक जिम्मेदारी और स्थानीय स्तर पर नेतृत्व का विकास अत्यंत आवश्यक है।

कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को संदेश दिया गया कि परियोजना के अंतर्गत विकसित सभी गतिविधियों एवं सुविधाओं को वे अपनी सामुदायिक संपत्ति समझें और उनके संरक्षण, संचालन तथा रखरखाव में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।

यह पहल ग्रामीण समुदाय को विकास प्रक्रिया का सहभागी बनाने के साथ-साथ उनमें स्वामित्व की भावना विकसित करने, सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

विधानसभा चुनाव-2027: हरिद्वार में ईवीएम-वीवीपैट जागरूकता अभियान शुरू

- 16 नवंबर से शुरू हुआ जन-जागरूकता कार्यक्रम, 11 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगी मोबाइल डेमोंस्ट्रेशन वैन
- राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ईवीएम-वीवीपैट को अलग स्ट्रांग रूम में रखा गया
- डेमोस्ट्रेशन सेंटर पर आमजन को मिलेगा मतदान प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण

के.के.पी संवाददाता

हरिद्वार। जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार विधानसभा के आगामी सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के तहत जनपद हरिद्वार में ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जन-जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। यह अभियान 16 नवंबर 2026 से प्रारंभ हो चुका है। इसके तहत जनपद के सभी 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आमजन को ईवीएम एवं वीवीपैट



के माध्यम से मतदान करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने अवगत कराया है कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ईवीएम एवं वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) पूरी होने के बाद प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए कुल 181 ईवीएम (बीयू, सीयू एवं वीवीपैट) चिन्हित की गई हैं। इनमें से 23 बैलेट यूनिट (बीयू-23), 23 कंट्रोल यूनिट (सीयू-23) और 23 वीवीपैट को अलग स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। यह प्रक्रिया मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में निर्धारित मानकों एवं प्रोटोकॉल के अनुरूप पूरी की गई। प्रशिक्षण के लिए चिन्हित मशीनों की सूची भी राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है। मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रदर्शन दिखाने के लिए प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय पर ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर (ईडीसी) स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर आम नागरिक ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। इसके साथ ही जनपद के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में मोबाइल डेमोंस्ट्रेशन वैन (एमडीवी) तैनात की गई हैं। ये वैन मतदान केंद्रों, गांवों, मोहल्लों, वार्डों एवं विभिन्न क्लस्टरों तक पहुंचकर मतदाताओं को जागरूक करेंगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने तक यह व्यावहारिक जागरूकता अभियान जारी रहेगा।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2026 के सफल एवं निष्पक्ष आयोजन को लेकर बैठक आयोजित

- जनपद के 52 परीक्षा केंद्रों पर 20,958 परीक्षार्थी होंगे शामिल, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न होगी परीक्षा
- प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 02 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं एक केंद्र प्रभारी की तैनाती, सुरक्षा के लिए 05 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात
- परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, सभी केंद्रों पर जैमर लगाने के निर्देश
- परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में लागू रहेगी धारा-163, अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने सेक्टर मजिस्ट्रेटों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

के.के.पी संवाददाता

हरिद्वार। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं



नकलविहीन संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सेक्टर मजिस्ट्रेटों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा के सफल संचालन, सुरक्षा व्यवस्था, गोपनीय परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन तथा परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में जानकारी दी गई कि जनपद में कुल 52 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 20,958 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें रुड़की क्षेत्र में 16 तथा हरिद्वार क्षेत्र में 36 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगी।परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर दो सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं एक परीक्षा केंद्र प्रभारी की तैनाती की गई है। इसके साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पांच सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नकल एवं अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की गोपनीयता एवं शुचिता बनाए रखने के लिए सभी अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता एवं जिम्मेदारी से निर्वहन करें।

मेघालय के जल और वन संरक्षण मॉडल को समझ रहा उत्तराखंड का दल, चम्पावत की समितियों को मिलेगा लाभ

के.के.पी संवाददाता

SARRA मुख्यालय के अधिकारियों और चम्पावत की धारा-नौला संरक्षण समिति के सदस्यों का शिलांग में तीन दिवसीय अध्ययन भ्रमण

कार्बन क्रेडिट, बायोचार प्लांट और वन संरक्षण के बदले मिलने वाले आर्थिक प्रोत्साहन (PES) मॉडल की बारीकियां सीखीं

उत्तराखंड के पारंपरिक जल स्रोतों (धारा-नौला) के पुनर्जीवन और सामुदायिक वन संरक्षण को नई दिशा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग्स एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी (SARRA) और जनपद चम्पावत की धारा-नौला संरक्षण समितियों का एक संयुक्त दल मेघालय के दौरे पर है। 25 से 27 नवंबर तक शिलांग में आयोजित इस तीन दिवसीय अध्ययन भ्रमण में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वन और ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों सहित कुल 13 प्रतिनिधि शामिल हैं।



भ्रमण के दौरान मेघालय बेसिन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MBDA) और मेघालय बेसिन मैनेजमेंट एजेंसी (MBMA) के अधिकारियों ने दल को राज्य में संचालित प्रमुख परियोजनाओं–जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) द्वारा वित्तपोषित 'MEGALIFE' और जर्मन विकास बैंक (KfW) द्वारा वित्तपोषित 'MEGARISE' की कार्यप्रणाली से अवगत कराया।

वन बचाने पर हर साल 10,000 प्रति हेक्टेयर का प्रोत्साहन

दल ने MEGALIFE परियोजना के तहत संचालित 'पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज' (PES) मॉडल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मॉडल के तहत स्थानीय स्तर पर गठित समितियों (जिनमें 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है) को प्राकृतिक वन संरक्षण के बदले 10,000 प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। शिलांग के संबंधित ग्राम की समिति ने इस पहल से 46-47 हेक्टेयर वन क्षेत्र को संरक्षित किया है और वर्तमान में समिति के खाते में सामुदायिक विकास के लिए लगभग 15 लाख की राशि जमा है।

बायोचार और कार्बन क्रेडिट से ग्रामीणों की आय बढ़ाने पर जोर

SARRA के उपनिदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी ने क्षेत्र में स्थापित बायोचार उत्पादन संयंत्र (Biochar Production Plant) का भी जायजा लिया। मई 2026 में MBDA, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (FPC) और निजी संस्था के त्रिपक्षीय समझौते से शुरू हुए इस पायलट प्रोजेक्ट के जरिए बायोचार उत्पादन और उससे मिलने वाले कार्बन क्रेडिट का सीधा लाभ स्थानीय समुदायों को देने पर काम चल रहा है। इस दौरान कोर कार्बन एक्स (Core Carbon X) के प्रतिनिधियों ने भी तकनीकी सहयोग प्रदान किया। भ्रमण दल ने मेघालय की एग्रोफॉरेस्ट्री (कृषि वानिकी) तकनीकों का भी अध्ययन किया। अधिकारियों का मानना है कि मेघालय का PES मॉडल और सामुदायिक सहभागिता उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर चम्पावत की धारा-नौला संरक्षण समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और जल स्रोतों के संरक्षण में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नरों का तबादला, 28 आईपीएस बदले



नोएडा। यूपी की योगी सरकार ने शुक्रवार को वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नरों का तबादला कर दिया। 28 आईपीएस अफसरों को बदला गया है। सबसे महत्वपूर्ण नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का नाम है। उन्हें गाजियाबाद भेज दिया गया है। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ को नोएडा भेजा गया है। कई डीआईजी भी बदल दिए गए हैं। अयोध्या और मुरादाबाद के एसएसपी को भी बदला गया है। बताया जाता है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर तीन साल से ज्यादा जमे अफसरों को हटाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं।

वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को प्रयागराज का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। वाराणसी में अब किरण एस को पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। किरण एस अभी तक पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया को अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उप्र लखनऊ के पद पर भेजा गया है। बरेली की अपर पुलिस महानिदेशक रमित शर्मा को इसी पद पर लखनऊ भेजा गया है। लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक प्रवीण कुमार को बरेली में अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है।

अलीगढ़ के डीआईजी प्रभाकर चौधरी को इसी पद पर लखनऊ भेजा गया है।

सहारनपुर के डीआईजी अभिषेक सिंह को आगरा भेजा गया है। आगरा के डीआईजी शैलेश कुमार पाण्डेय को अलीगढ़ में तैनाती दे दी गई है। डीआईजी तकनीकी सेवाएं आशीष तिवारी अब सहारनपुर परिक्षेत्र में डीआईजी होंगे। अयोध्या के एसएसपी डॉ0 गौरव ग्रोवर को मुरादाबाद का एसएसपी बना दिया गया है। मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल को अयोध्या का एसएसपी बनाया गया है।

नोएडा की पुलिस उपायुक्त श्रीमती सुनीति को लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। बरेली में सेनानायक के पद पर तैनात आकाश तोमर को पुलिस अधीक्षक डॉ0 बीआर अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद भेजा गया है।

अखिलेश के मेनिफेस्टो से मुसलमान गायब, बरेली के मौलाना बोले- सपा मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझ रही



बरेली। समाजवादी पार्टी का मेनिफेस्टो जारी होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मेनिफेस्टो में मुस्लिम समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा कि मेनिफेस्टो में शिक्षा, रोजगार, बिजली, सड़क और विकास जैसे मुद्दों का जिक्र किया गया है, लेकिन मुसलमानों की समस्याओं और उनके विकास को लेकर कोई ठोस बात नहीं कही गई। मौलाना ने सवाल उठाया कि जब समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वोट चाहिए तो उनके हितों को मेनिफेस्टो में जगह क्यों नहीं दी गई।

मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव के पांच साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आज अखिलेश यादव अपने मेनिफेस्टो में गुंडागर्दी और बदमाशी खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री रहते प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, यह किसी से छिपा नहीं है। मौलाना ने उस दौर के चर्चित नारों का जिक्र करते हुए सपा के पुराने कार्यकाल पर निशाना साधा।

मौलाना ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज को केवल वोट देने वाला वर्ग समझती है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति, शिक्षा में पिछड़ापन और रोजगार जैसी समस्याओं पर मेनिफेस्टो में चर्चा होनी चाहिए थी। मुस्लिम समाज के विकास के लिए ठोस योजनाओं और आश्वासनों की जरूरत है, लेकिन इन मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने सपा के मेनिफेस्टो को खारिज करते हुए इसे बकवास और वाहियात करार दिया।

योगी नहीं तो यूपी नहीं...संजय राउत अचानक क्यों करने लगे तारीफ? बताया हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा



नई दिल्ली। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले राज्यसभा सांसद संजय राउत फिर चर्चा में है. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के सांसद ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की है. विरोधी खेमे से होने के बाद भी उन्होंने सीएम योगी को काबिल आदमी और हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बताया. उनके इस बयान ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है. संजय राउत पिछले कुछ समय में लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे हैं, लेकिन लंबे समय बाद ऐसा मौका दिखा है, जब उन्होंने बीजेपी नेता की खुलकर तारीफ की है.

योगी नहीं तो यूपी भी नहीं: संजय राउत

संजय राउत ने कहा 'अगर योगी जी ने खुद को सीएम चेहरे के तौर पर पेश किया है, तो यह तारीफ के काबिल है. वे एक सक्षम व्यक्ति हैं और हम भी योगी जी को पसंद करते हैं. योगी जी हिंदुत्व का एक ऐसा चेहरा हैं जो सबसे ऊपर हैं और अगर योगी नहीं तो यूपी भी नहीं. अगर योगी जी ने ऐसा कहा है तो उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुमत हासिल करेगी और चुने गए विधायकों में से ज्यादातर उनका समर्थन करेंगे. योगी जी को पूरा भरोसा है कि उन्हें यूपी में बहुमत मिलेगा और उस बहुमत में सबसे ज्यादा विधायक योगी जी का समर्थन करने वाले होंगे. क्योंकि विधायक दल ही अपने नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर चुनता है.'

संजय राउत पहले भी कर चुके हैं योगी की तारीफ

संजय राउत का यह बयान इसलिए भी खास है क्योंकि शिवसेना (UBT) इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है. इसके बावजूद राउत ने योगी की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी. इसके अलावा यह कोई पहला मौका नहीं है, जब संजय राउत ने सीएम योगी की तारीफ की हो.

क्यों बदले-बदले नजर आ रहे अखिलेश यादव? 3 घोषणापत्र, 75 जिलों का टारगेट, यूपी चुनाव में अलग रणनीति की झलक



नई दिल्लीः समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पार्टी का घोषणापत्र जारी कर दिया. यूपी से 10 सालों से सत्ता से दूर सपा ने इस बार पुरानी रणनीति में बदलाव कर चुनाव के करीब तीन महीने पहले पार्टी का घोषणापत्र जारी किया है. पीडीए के प्रणपत्र नाम के इस मेनिफेस्टो में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, बेरोजगारों को 5 हजार रुपये भत्ता, 25 लाख सरकारी नौकरी के साथ महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये पेंशन शामिल है.

पार्टी ने विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पर आनन-फानन में मेनिफेस्टो जारी करने की बजाय इस बार तीन चरणों में अपना घोषणापत्र सामने रखने की रणनीति अपनाई है. इसका पहला चरण संविधान दिवस पर पार्टी के मुख्य घोषणापत्र के साथ हुई. शीर्ष नेतृत्व, जातीय गठबंधन और आखिरी वक्त चुनावी घोषणाओं से इतर इस बार पार्टी ने लंबे विचार-विमर्श, विशेषज्ञों की राय और आम जनता के फीडबैक के आधार पर ये घोषणापत्र तैयार किया है.

अखिलेश यादव ने प्रदेश के सभी 75 जिलों की जरूरतों के आधार पर टारगेटेड घोषणापत्र तैयार करने की रणनीति इस बार अपनाई. किसानों, कारोबारियों, निवेशकों और वंचित वर्ग के बीच चर्चा, सीधे फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार की.लीक से हटकर आम वोटरों के फीडबैक की झलक मेनिफेस्टो में दिख रही है. पहले से सबक लेते हुए समाजवादी पार्टी चुनावों से काफी पहले तीन घोषणापत्र जारी करेगी. पहला दस्तावेज युवाओं, शिक्षा, नौकरियों, किसानों, सामाजिक न्याय, उद्योग, दलित मुद्दों, कानून-व्यवस्था और एमएसएमई (MSMEs) पर केंद्रित होगा. दूसरा दस्तावेज महिलाओं पर केंद्रित होगा.

'वो संविधान के संरक्षक'; अचानक बदल गए कांग्रेस के सुर, जिससे तोड़ा नाता, उसी की करने लगी बड़ाई



नई दिल्ली। संसद की फिर से बैठक बुलाने के केंद्र सरकार के ऐलान और आज (शुक्रवार, 27 नवंबर को) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राजनीति एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 30 नवंबर से शुरू हो रहे लोकसभा के चार दिवसीय और राज्यसभा की दो दिवसीय बैठक के दौरान सरकार परिसीमन बिल पेश कर सकती है। लंबे समय से अटकलें हैं कि तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी और लंबे समय तक कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन में सहयोगी रही द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) इस बिल का समर्थन कर सकती है। हालांकि, DMK प्रमुख एम के स्टालिन ने अपनी स्थित साफ करते हुए दो टूक कहा, ''हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और न ही इस पर कोई समझौता हो सकता है।'' स्टालिन ने शुक्रवार को एक बार फिर दोहराया कि किसी भी परिस्थिति में लोकसभा में तमिलनाडु की मौजूदा 7.18 प्रतिशत सीटों की हिस्सेदारी को कम नहीं किया जाना चाहिए। ड्रब्ब्य प्रमुख ने कहा कि राज्यों के बीच संसदीय प्रतिनिधित्व का मौजूदा अनुपात 1971 की जनगणना पर आधारित है और इसे इसी आधार पर बनाए रखने की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने मांग की कि अगले 25 सालों तक भी इसी आधार पर लोकसभा की सीट का परिसीमन किया जाना चाहिए। स्टालिन के इस रुख से विपक्षी इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी राहत की सांस ली है लेकिन खतरा टला नहीं है।

इस बात की भी अटकलें हैं कि परिसीमन बिल के विरोध में ड्रब्ब्य लोकसभा से वॉकआउट कर सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार का पलड़ा भारी हो सकता है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं और सभी सहयोगी दलों से संपर्क साधा जाने लगा है।

श्रीनगर में अभी दुनिया की सबसे जहरीली हवा? दिल्ली से 3 गुना ज्यादा QI, माइनस 2 डिग्री गया पारा



श्रीनगर। जिस श्रीनगर को हम झीलों, पहाड़ों और हिमालय की साफ-सर्द हवाओं के लिए जानते हैं, वह इस समय जहरीली हवाओं की वजह से दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है. खबर लिखे जाने के वक्त AQI.in नाम के एक थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म के आंकड़ों के अनुसार, 27 नवंबर को दोपहर 12 बजे शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 558 था, जिससे यह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया. दूसरी तरफ नई दिल्ली का AQI 190 बताया गया था.

इस बीच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के AQI आंकड़ों में काफी अंतर देखने को मिला. CPCB के सरकारी आंकड़ों के अनुसार कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में AQI 145 था, जो 'मध्यम' या मॉडरेट श्रेणी में आता है.

अनंत सिंह की बेटी की शादी में हुई घुड़दौड़ का फाइनल अभी बाकी, इन 6 घोड़े मालिकों में से किसी एक को मिलेगी THAR



मोकामा। मोकामा के लदमा गांव में आयोजित घुड़दौड़ प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला अभी नहीं हुआ है. यह प्रतियोगिता पूर्व विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी के मौके पर आयोजित की गई थी. अब तक हुई सभी राउंड और सेमीफाइनल के बाद 6 घोड़ों का चयन फाइनल के लिए किया गया है. आयोजकों का कहना है कि यही 6 घोड़े अंतिम दौड़ में हिस्सा लेंगे. हालांकि फाइनल की तारीख और आयोजन को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.

शुक्रवार को एनडीटीवी से बातचीत में आयोजन से जुड़े जय सिंह ने कहा, 'फिलहाल सभी लोग शादी के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं. जब शादी से पूरी तरह फुर्सत मिल जाएगी, तब फाइनल राउंड कब और किस तरह कराया जाएगा, इस पर फैसला लिया जाएगा. इसके बाद मीडिया को भी फाइनल डेट की जानकारी दी जाएगी. अब तक हुई रेस के बाद जिन 6 घोड़ों ने फाइनल में जगह बनाई है, उनमें भोजपुर के संजय यादव का घोड़ा बाली, सिवाल के प्रवीन ठीकदार का पंचकल्याण, खगड़िया के प्रिंस यादव का उस्मान, खगड़िया के रणवीर यादव की घोड़ी सब्जा, खगड़िया के रामकुमार यादव का राजा और रांची के शेरावत अली का घोड़ा रांची एक्सप्रेस शामिल हैं.

आयोजकों के अनुसार, गुरुवार को हुई रेस देखने के लिए लदमा गांव में करीब 3 से 4 लाख पहुंच गए थे, जिससे हालात बिगड़ गए थे.

यूपी पंचायत चुनाव 6 महीने और टले, ग्राम प्रधान संभालेंगे प्रशासक की जिम्मेदारी



लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव छह महीने और आगे बढ़ाए जाने पर मुहर लग गई है. यूपी में पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हुआ था और तमाम वजहों से इसे छह महीने बढ़ाया गया था. ये अवधि 27 नवंबर को खत्म हो रही थी और इसके पहले ही इसे छह महीने और विस्तार दे दिया गया. यूपी में पंचायत मतदाता सूची अपडेट न होने, पंचायतों में ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट तैयार न होने जैसी वजहों से पंचायत चुनाव में देरी हुई है. अब ग्राम प्रधान छह महीने और जिम्मेदारी संभालेंगे. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं.

यूपी में 57694 ग्राम पंचायतें हैं. इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत और 75 जिलों की जिला पंचायत भी हैं. पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपने में अभी और देरी कर सकता है, क्योंकि 75 जिलों में अभी 25 से ज्यादा जिले बाकी हैं, जहां जमीनी सर्वे पूरा कर उसे पिछड़ा वर्ग के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन पर रिपोर्ट देनी है. वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश जारी किया था. ऐसे में सरकार के सामने संवैधानिक मजबूरी थी कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए अध्यादेश लाया जाए. यूपी पंचायत चुनाव का कार्यकाल आगे बढ़ाने का आदेश 26 नवंबर से ही लागू हो गया. ऐसे में प्रशासक के तौर पर ग्राम प्रधान छह माह और जिम्मेदारी संभालेंगे. चूंकि यूपी में फरवरी-मार्च में बोर्ड परीक्षाएं होंगी और ठीक उसके बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है. फिर नई सरकार के कामकाज संभालने में कुछ वक्त लग सकता है. ऐसे में पंचायत चुनाव मई-जून में ही संभावित हो सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में ओबीसी कमीशन अभी हर जिले में जाकर ओबीसी के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन पर रिपोर्ट तैयार करने में जुटा है. समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकाल का विस्तार भी किया गया है.

सिम चोरी कर बैंक खाते से उड़ाए 2.66 लाख रुपये

बाइक सवार तीन युवकों ने दुकानदार को बातों में उलझाकर मोबाइल से निकाला सिम, प्राथमिकी दर्ज

सितारगंज (दीपक भारद्वाज)/नानकमत्ता। साइबर ठगों ने अब ठगी का नया तरीका अपनाते हुए एक दुकानदार के मोबाइल से सिम कार्ड चोरी कर उसके बैंक खाते से 2.66 लाख रुपये निकाल लिए। बाइक सवार तीन युवकों ने दुकानदार को बातचीत में उलझाकर इस वारदात को अंजाम दिया। खाते से बड़ी रकम निकलने की जानकारी मिलने पर पीड़ित के होश उड़ गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार ग्राम डोहरा सिसईखेड़ा निवासी प्रहलाद सिंह बिष्ट की दुकान पर बीते 19 नवंबर को बाइक सवार तीन युवक पहुंचे थे। तीनों युवक किसी काम के बहाने उनसे बातचीत करने लगे। इसी दौरान युवकों ने उन्हें बातों में उलझा लिया।

आरोप है कि मौका पाकर युवकों ने दुकान के काउंटर पर रखे उनके मोबाइल फोन से सिम कार्ड निकालकर चोरी कर लिया। दुकानदार को उस समय सिम चोरी होने की भनक तक नहीं लगी। कुछ समय बाद उन्हें सिम कार्ड चोरी होने की जानकारी हुई तो उन्होंने इसके दुरुपयोग की आशंका जताते हुए तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क किया। वहां से उन्हें संबंधित कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना देकर अपना सिम कार्ड बंद कराया, ताकि उसका गलत इस्तेमाल न हो सके। पीड़ित ने सिम चोरी होने की जानकारी अपने बैंक को भी दी।

105 नहीं, उससे ज्यादा सीट चाहिए... खरगे की डांट के बाद भी नहीं माने इमरान मसूद, सपा पर फिर हमला



नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस को आगामी चुनाव में 105 से अधिक सीटें मिलनी चाहिए. उन्होंने याद दिलाया कि 2017 में कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि उस समय पार्टी की स्थिति कहीं अधिक कमजोर थी. मसूद ने समाजवादी पार्टी को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को पर्याप्त और जीतने योग्य सीटें दी जानी चाहिए, क्योंकि गठबंधन में सम्मान और साझेदारी दोनों जरूरी हैं. मसूद का यह बयान तब आया है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपनी बयानबाजी के लिए मसूद को सार्वजनिक मंच से हिदायत दे चुके हैं. खरगे ने कहा था कि हमें सिर्फ बातों के बजाय काम पर ध्यान देना चाहिए. जितना ज्यादा मिलकर काम करेंगे, उतनी ही ज्यादा तरक्की करेंगे. इमरान मसूद ने कहा कि '105 सीटें नहीं, 105 से ऊपर. 2017 में हमने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था. उस समय हमारी स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन अब हम कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं. उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा-कांग्रेस सीट बंटवारे पर इमरान मसूद ने कहा कि 2022 में मुसलमानों ने एकतरफा और आंख बंद करके वोट दिया था, फिर भी हम क्यों हारे? उस जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा आपके ऊपर है. आप हम पर भरोसा कर रहे हैं और हम तैयार हैं. हमने कहा था कि संख्या भी चाहिए और अच्छी सीटें भी चाहिए. आपने हमें ये 26 सीटें दी हैं, तो उसके नतीजों की जिम्मेदारी भी आप लीजिए.

स्वामी/ प्रकाशक / मुद्रक
प्रमोद कुमार ने जय माँ गंगा प्रिंटर्स, हरिद्वार से मुद्रित कराकर कार्तिकेय कॉलोनी, फेस-3, दर्पण स्कूल वाली गली, निकट हनुमान मंदिर, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी जनपद-नैनीताल (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया।
सम्पादक
प्रमोद कुमार
मो.7830201066
सह-सम्पादक
दया जोशी
मो.9412135616